—सुविचार—
'मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं'

साप्ताहिक
प्रमोदन
प्रति गुरूवार

डाक पंजीयन- छ.ग./ दुर्ग/116/2022-24

भिलाई वर्ष-08, अंक : 32 13 जुलाई से 19 जुलाई 2023 पृष्ठ-08 मूल्य : पांच रुपए

पढ़ें जीएसटी काउंसिल की बैठक के बड़े फैसले

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो पर अब 28प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें मिलेंगी सस्ती

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने चार वस्तुओं पर जीएसटी को कम करने के साथ ही कैंसर के लिए उपयोगी दवायें एवं खाने की वस्तुओं एवं निजी कंपनियों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया है जबकि कसिनो, हॉर्स रेस के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले रिफ्रेशमेंट पर टैक्स 18त्न से घटाकर 5त्न कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की 50वीं बैठक के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनकूक्ड और अनफ्रायड् स्नैक पैलेट्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया गया है। इसी तरह से फिश सॉलूब्ल पेस्ट पर भी जीएसटी को 18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सज्जात्मक जरी धागे पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरक्त एलडी स्लैग पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से कैंसर की बीमारी में उपयोगी डिनुटुक्सिंब (क्यारजिबा) दवा को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात करने पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। इसी के साथ दुलर्भ बीमारियों के लिए उपयोगी दवाओं और खाने पीने की वस्तुओं के आयात पर भी आईजीएसटी नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कसिनो, हॉर्स रेस के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। हालॉकि गोवा और सिक्किम ने कसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी का विरोध किया था लेकिन परिषद ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन की परिभाषा को पुन: परिभाषित किया गया है और अब 1500 सीसी क्षमता से बड़ा इंजन, चार मीटर से अधिक लंबे यात्री वाहन और बगैर भाड़ के 170 मिलीमीटर और इससे अधिक ग्रांउड क्लियरेंस वाले वाहनों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिभार लगेगा। इसमें सभी यूटिलिटी वाहन भी आयेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद आदि जिस पर कानूनी रूप से खुदरा विक्रय मूल्य अंकित करने की जरूरत नहीं पर 31 मार्च 2023 तक जो कर लग रहा था उस पर अब क्षतिपूर्ति कर लगाने का आदेश जारी किया जायेगा।

मां के आदर्शों पर चलकर छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास के लिए कर रहा हूं निरंतर कार्य : भूपेश बघेल

ग्राम भरदा टटेंगा में माता बिंदेश्वरी पार्क एवं प्रतिमा का किया अनावरण

रायपुर (प्रमोदन)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती बिंदेश्वरी देवी हमेशा कहा करती थी कि गांव, गरीब एवं किसानों के उन्नति से ही छत्तीसगढ़ एवं देश की उन्नति होगी। श्री बघेल ने कहा कि माँ के आदर्शों को आत्मसात् कर वे छत्तीसगढ के चहुंमुखी विकास एवं समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम भरदा टटेंगा में आयोजित माता बिंदेश्वरी देवी बघेल पार्क के लोकार्पण एवं प्रतिमा के अनावरण समारोह के अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। श्री बघेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक आत्मनिर्भर एवं खुशहाल राज्य के रूप में उभरा है। श्री बघेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पवित्र सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ग्राम भरदा टटेंगा में नव निर्मित माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क के समीप खरखरा नदी में पचरी निर्माण, बोटिंग व्यवस्था एवं सौंदर्यीकरण तथा बिंदेश्वरी बघेल पार्क में सामुदायिक हॉल के निर्माण हेतु 50.50 लाख रुपये, भरदा पुल से मुख्य मार्ग जेवरतला तक 3.50 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु 65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इसी तरह उन्होंने ग्राम भरदा में कैलाश धाम से मुक्ति धाम मार्ग के सीमेंटीकरण तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला टटेंगा के उन्नयन करने की भी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि ग्राम भरदा टटेंगा के ग्रामीणों द्वारा राज्य में लागू की गई किसान हितैषी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु राशि एकत्र कर माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क एवं मूर्ति का निर्माण कराया गया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ग्राम भरदा टटेंगा के ग्रामीणों को उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती बिंदेश्वरी देवी के नाम से पार्क एवं प्रतिमा निर्माण करने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने ग्राम भरदा टटेंगा में बिंदेश्वरी पार्क एवं प्रतिमा की स्थापना के लिए ग्राम वासियों के साथ.साथ जनपद सदस्य श्री राजेश साहू के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, संसदीय सचिव एवं क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद, संजारी बालोद की विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनादेवी देशलहरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मिथलेश निरोटी, जनपद अध्यक्ष जागृत सोनकर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती चंद्रप्रभा सुधाकर एवं श्रीमती मीना सत्येंद्र साहू, नगर पालिका बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

उद्धव ठाकरे ने दोहराया, चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल का नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं

अमरावती। शिवसेना-यूबीटी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह दोहराते हुए कि 'शिवसेना' उनकी पार्टी का नाम है, सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) के पास इसका नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं है। आज दोपहर में यहां मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास किसी राजनीतिक पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि 'शिवसेना' नाम उनके दादा केशव सीताराम ठाकरे उर्फ प्रबोधनकर ठाकरे ने दिया था और वह किसी को भी इसे 'चुराने' की इजाजत नहीं देंगे। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले एक धड़े के बाहर चले जाने और फिर उसी महीने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेने से शिवसेना अलग हो गई थी। इस साल फरवरी में चुनाव आयोग ने पार्टी में विभाजन को औपचारिक रूप दिया था और सीएम शिंदे के नेतृत्व वाले अलग गुट को 'शिवसेना' नाम और उसका निशान 'धनुष-बाण' दे दिया था।

चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश में ठाकरे गुट को एक संशोधित नाम 'शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे' और निशान 'जलती मशाल' आवंटित किया गया था। ठाकरे ने गरजते हुए कहा, भारत निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल का नाम कैसे बदल सकता है? मैं पार्टी और उसके नाम को चुराने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह मुद्दा फिर से गरमा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को शिवसेना-यूबीटी की याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है, जिसमें पार्टी के नाम और चिह्न पर चुनाव आयोग के फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि शिवसेना बनाम शिवसेना मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 11 मई के फैसले के मद्देनजर चुनाव आयोग का आदेश पूरी तरह से अवैध है। याचिका में कहा गया है कि चूंकि चुनाव आने वाला है, इसलिए शिंदे गुट अवैध रूप से मूल पार्टी के नाम और प्रतीक का उपयोग कर रहा है, इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।

बंगाल में हत्याओं की घटनाओं से प्रशासन मुकर नहीं सकता है: संबित पात्रा

नई दिल्ली/कोलकाता । जब बंगाल में बंगाल में पंचायत चुनाव की गिनती हो रही थी तब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जम कर ममता सरकार पर हमला बोला और तमाम गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। अब तक पंचायत चुनाव में 45 लोगों की जान जा चुकी है।

जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 52 लोगों की जान गई थी। यहां केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ही हत्या नहीं हुई, अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। तल्ख तेवर में भाजपा प्रवक्ता ने कहा, अगर यह दृश्य बीजेपी शाषित राज्य में देखने को मिला होता, तो अबतक हाहाकार मच गया होता। अब राहुल गांधी कहां हैं...? वह मोहब्बत की दुकान खोलने वाले थे। राज्य सरकार ने संवेदनशील बूथ की सही संख्या नहीं दी, जितने लोग मारे गए हैं, इसमें राज्य के ज़िम्मेदार लोग शामिल हैं। फायरिंग, बमबारी मतपेटी को जलाया जा रहा है। ये सारे नेता, जो हाथ पकड़-पकड़ कर राज्यों में खड़े होते हैं, कहां हैं ये सारे नेता? कहां हैं लालू प्रसाद यादव, कहां हैं नीतीश कुमार और कहां हैं मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? उन्होंने कहा, जिस भूमि से कभी वन्दे मातरम् के शब्द उपजे थे, आज उसी भूमि पर जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वह अपने आप में अप्रत्याशित है। इससे पहले इस प्रकार की हिंसा न हमने सुनी थी और न ही देखी थी. चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची बन चुके हैं।

दो अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा एससी, सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनाएगी फैसला

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच दो अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर 23 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

अदालत ने कहा कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल करा दें, उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर कर कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे क्षेत्र ने शांति, विकास और संपन्नता का अभूतपूर्व युग देखा है।

केंद्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। जेएंडके में पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर हो गई हैं। इसके अलावा आतंकी ईको-सिस्टम भी लगभग खत्म हो गया है। ये सब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण संभव हो पाया है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। अनुच्छेद-370 हटाकर केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विभाजित कर दिया था।

हाईकोर्ट की राज्य चुनाव आयोग को फटकार, कहा- केवल हो रहा है एक दूसरे पर दोषारोपण

कोलकाता। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर उपजे हालात किस स्तर पर संगीन है इसका अंदाजा आज कलकत्ता हाई कोर्ट के इस टिप्पणी से लगाया जा सका कि उच्च न्यायालय किस कदर क्षोभ में है। पंचायत चुनाव के दौरान 8 जुलाई से हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आयोग से सवाल किया है कि हाईकोर्ट रजिस्ट्री को हिंसा का आरोप लगाने वाले 44 से ज्यादा ईमेल मिले हैं। आप इन हालात पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सके?। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने आरोप-प्रत्यारोप करने वालों से कहा- पहला दूसरे को दोष दे रहा है। दूसरा किसी और को दोष दे रहा है। फिर हमने जो इतने सारे आदेश जारी किए थे, उनका क्या मतलब है? बता दे कि , राज्य सरकार ने आज कोर्ट में चुनावी हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया कि नामांकन वापसी के दौरान कोई अवैधता नहीं हुई, साथ ही यह भी कहा गया कि नामांकन वापसी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी। एक दिन पहले कोर्ट ने राज्य सरकार और सुरक्षा बलों से हिंसा पर स्टेट रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही यह भी निर्देश दिया था एफआईआर दर्ज और पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी करानी होगी। बंगाल में 8 जुलाई को हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं के बीच 80.71त्न मतदान हुआ था।

यमुना में बाढ़ : पानीपत के गांव नन्हेड़ा में टूटा बांध; 6 गांव में पानी भरा

हिमाचल में 1239 सड़कें बंद, 1400 बस रूट निलंबित, परवाणू से दूध-ब्रेड की गाड़ियां वापस भेजीं

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 72 घंटे से ज्यादा की मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। दो दिन के भीतर 21 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को आठ और लोगों की मौत हो गई है जबकि छह उफनती नदियों और नालों में बह गए हैं। बीते 24 जून को हिमाचल पहुंचा मानसून अब तक 63 लोगों की जान ले चुका है। भूस्खलन के चलते प्रदेश में मंगलवार सुबह 10-00 बजे तक 1239 सड़कें यातायात के लिए बाधित थीं। 2577 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। 1418 जल आपूर्ति योजनाएं भी बंद पड़ी हैं। संबंधित विभाग इनकी बहाली में जुटे हैं। शिमला में सबसे ज्यादा 581,

मंडी 200, चंबा 116, सिरमौर 101, हमीरपुर व लाहौल-स्पीति में 97-97 सड़कें बंद पड़ी हैं।

इसी तरह मंडी में 673, शिमला 821, सिरमौर 447, लाहौल-स्पीति 206 व किन्नौर में 261 बिजली ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। वहीं, भारी बारिश के चलते श्रीखंड महादेव की पवित्र यात्रा भी स्थगित कर दी है। बीच राह में टेंटों में फंसे यात्रियों को मौसम साफ होते ही वापस लाया लाएगा। सोमवार को कुल्लू जिला में फिर बादल फटा है। लगघाटी के फलाण में बादल फटने से 100 बीघा जमीन बह गई है। सरकारी तार स्पेन भी क्षतिग्रस्त हो गया है।

यमुना में बाढ़ : पानीपत के गांव नन्हेड़ा में टूटा बांध; 6 गांव में पानी भरा

पानीपत 11 जुलाई ,(आरएनएस)। पहाड़ों में हुई बारिश के बाद यमुना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। रात दो बजे गांव नन्हेड़ा के पास बांध टूट गया। छह गांव पानी से लबालब हो गए। इन गांवों का पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। इन गांवों में हजारों लोग फंसे हैं। प्रशासन इनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। यहां राहत कार्य जारी हैं। 30 एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है। रात करीबन दो बजे यमुना में 2.30 क्यूसेक पानी पहुंचा था। पानी के दबाव में ये बांध टूटा है। इससे पहले 2013 में भी इस स्थान पर बांध टूटा था। पहाड़ों व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात से यमुना उफान पर है। यह चेतावनी के निशान को पार कर गई है। इससे यमुना के तटीय क्षेत्र में 30 हजार एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। छह गांव डूब चुके हैं। नौ गांवों में पानी जाने का भय बना हुआ है। सनौली गोशाला में भी पानी पहुंच चुका है। यहां से 110 गोवंशों को निकाला जा चुका है। प्रशासन किसानों की डूबी फसल का आंकलन भी कर रहा है। हथिनीकुंड बैराज से सोमवार को यमुना में 2.58 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। मंगलवार सुबह को 232 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यहां से चेतावनी बिंदू 210 मीटर व खतरे का निशान 231. 500 मीटर पर आ गया है। अब यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।

संपादकीय

ईडी निदेशक के कार्यकाल बढ़ाने को बताया अवैध

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाये जाने को अवैध बताते हुए सरकार से उन्हें 31 जुलाई तक हटाने को कहा है। हालांकि, तीसरी बार बढ़ाया गया उनका कार्यकाल अभी 18 नवंबर तक था। कोर्ट ने सरकार से इस पद पर बीस दिन में नयी नियुक्ति करने को कहा है। कोर्ट का मानना है कि मिश्रा का तीसरा कार्यकाल बढ़ाया जाना अवैध है। दरअसल, कोर्ट पहले भी सरकार को कह चुकी थी कि संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार न बढ़ाया जाये। सरकार की दलील थी कि वे अभी मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी कर रहे हैं। जिसकी वजह से नई नियुक्ति के लिये सरकार कुछ समय चाहती है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने यह फैसला कॉमन कॉज नामक स्वयंसेवी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गत आठ मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। दरअसल, वर्ष 2021 में जब कोर्ट ने निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने से मना किया था तो इसके खिलाफ केंद्र सरकार 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव के लिये एक अध्यादेश लायी थी। इस संशोधन में प्रावधान रखा गया कि देश की महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों के निदेशक को पांच साल तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है। तदुपरांत केंद्र ने तीसरी बार संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया। हालांकि, कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने वाले कानून में बदलाव को वैध माना, लेकिन नियुक्ति को अवैध ठहराया। कोर्ट का मानना था कि किसी भी जांच एजेंसी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया जाना तार्किक होना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस ने भी याचिका दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि लंबे समय से विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने और राजनीतिक लाभ के लिये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती रही है। पिछले कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रवर्तन निदेशालय की ही रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं व कारोबारियों के लेनदेन में कथित अनियमितताओं की जांच ईडी कर कर रही थी। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। यही वजह है कि संजय मिश्रा के मामले में याचिका दायर करने वालों की दलील थी कि ईडी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और देश हित में उसे स्वतंत्र होना चाहिए। कोर्ट ने भी सवाल किया था कि क्या वजह है कि उसके आदेश के बावजूद मिश्रा का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं सरकार की दलील थी कि मिश्रा कई संवेदनशील व महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहे हैं, जिसे तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाना बाकी है। केंद्र के पक्षकार का तर्क था ईडी डायरेक्टर संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कई अहम मामलों की जांच देख रहे हैं। वे फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की समीक्षा में शामिल हैं जिसको लेकर अभी काफी काम किया जाना बाकी है। अतः उनका देश हित में पद पर बने रहना जरूरी है। साथ ही यह भी कि योग्य अफसर तलाशने में अभी वक्त लगेगा।

डेटा सुरक्षा की पहल संग्रहण और उपयोग में पारदर्शिता जरूरी

जैसे-जैसे हमारे जीवन में ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार हुआए डेटा सुरक्षा और व्यक्ति की निजता की सुरक्षा के लिये सख्त कानून की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की गई। खासकर पिछले कुछ वर्षों में धोखाधड़ी और डेटा के दुरुपयोग की घटनाएं लगातार बढ़ती रही हैं। सरकार ने अब इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। जिससे मानसून सत्र में विधेयक के संसद में पेश किये जाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, सरकार के भीतर और बाहर संगठनों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित कानून को लेकर कई उतार.चढ़ाव देखने को मिले हैं। दरअसलए केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया था और तुरंत एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया था। पैनल को अपनी रिपोर्ट पेश करने में करीब दो साल लग गये। जिसमें समिति ने सिफारिश की थी कि किसी भी प्रावधान के आवेदन में सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से जुड़ी छूट को लेकर पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किये जाने चाहिए। जिससे निजी डेटा के दुरुपयोग की आशंका को टाला जा सके। अंततः अगस्त 2022 में पुराने विधेयक को वापस ले लिया गया और तीन महीने बाद सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा जारी किया। फिर सार्वजनिक रूप से परामर्श आरंभ किया। मसौदे को लेकर तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई क्योंकि इसमें केंद्र द्वारा अधिसूचित संस्थाओं को नागरिकों का डेटा एकत्र करने और उसके उपयोग के उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण देने से छूट दी गई थी। दरअसल, जरूरत इस बात की है कि लोगों को आश्वस्त किया जाये कि नवीनतम मसौदे में सरकारी एजेंसियों को पूर्ण छूट नहीं दी गई है। साथ ही विधेयक में मानदंडों के उल्लंघन से जुर्माने के दायरे में उन्हें भी आना होगा।

बताया जा रहा है कि डिजिटल डेटा संरक्षण कानून निजी तथा सरकारी संस्थाओं पर समान रूप से भी लागू होगा। अब आईटी कंपनियों को यह जानकारी साझा करनी होगी कि वे नागरिकों की कौन सी सूचनाएं अथवा आंकड़े जुटा रही हैं और कितना संग्रहण कर रही हैं तथा कितना किसी अन्य के साथ साझा कर रही हैं। यह इसलिये भी जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में नागरिकों के आधार कार्ड व पैन कार्ड से संबंधित डेटा चोरी होने, साझा करने तथा लीक करने के मामले लगातार प्रकाश में आते रहे हैं। संदेह की सुई देशी.विदेशी कंपनियों की तरफ घूमती रही है। सख्त कानून के अभाव में सरकार भी कार्रवाई करने में असहाय नजर आती रही है। इतना ही नहींए कई सुविधा प्रदाता कंपनियों के सर्वर तक विदेशों में स्थित होते हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेशों में रखे डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर आम उपभोक्ता जब कोई एप डाउनलोड करता है तो हमारी निजी जानकारी तक पहुंचने की अनुमति मांगी जाती है। हमारे फोन पर लगातार आने वाली व्यावसायिक कॉल इस बात का संकेत हैं कि हमारे फोन नंबर विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों को बेचे गये हैं। निस्संदेह, अब डेटा संरक्षण कानून बनने के बाद इन कंपनियों को जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है इससे उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता आएगी। दरअसल, हमारे देश में उपभोक्ताओं की निजता व डेटा सुरक्षा के लिये पहल करने में बहुत देर हुई है। विकसित देशों ने बहुत पहले ही अपने नागरिकों के हितों के संरक्षण की दिशा में कदम उठा लिये थे। जिसके चलते आईटी कंपनियां नागरिकों के डेटा के दुरुपयोग के बार में कोई कदम नहीं उठा सकती क्योंकि इसको लेकर कड़े प्रावधानों के चलते उन्हें भारी मुआवजा देने के लिये बाध्य किया जाता है। विश्वास है कि सरकार नये डेटा सुरक्षा विधेयक में पर्याप्त सुरक्षा प्रावधानों को सुनिश्चित करेगी। ताकि भविष्य में लोगों की सहमति के बिना उनके डेटा का दुरुपयोग न किया जा सके। सरकार को समझना ही चाहिए कि लोगों की निजी सूचनाएं देश की बहुमूल्य संपदा है, जिसका संरक्षण प्राथमिकता के आधार पर हो।

आर्थिक मजबूती से शेयर बाजार को संबल

ऐसे वक्त में जब कोरोना संकट और रूस.यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात से वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं उबरने की कोशिश कर रही हैं, भारत का शेयर बाजार कुलांचें भर रहा है। बीते सोमवार को पहली बार सेंसेक्स का पैंसठ हजार के पार होना सुखद ही रहा। निफ्टी ने भी नई ऊंचाई तय की। दरअसल, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक नियामक वित्तीय संस्थाओं ने हाल में सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। निस्संदेह, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय तेजी से बढ़ रही है। जिससे विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। दरअसलए हाल के दिनों में महंगाई की दर में कुछ कमी दर्ज की गई, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ और कच्चे तेल के दाम में कमी से बाजार को संबल मिला। जिसका असर शेयर बाजार पर भी नजर आया। कहीं न कहीं दुनिया में भी मंदी से उबरने के संकेत नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक घरेलू बाजार में निवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों आए आंकड़ों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था का अधिकांश मापदंडों पर प्रदर्शन उत्साहवर्धक रहा है। जिसका प्रमाण जीएसटी संग्रह में आई तेजी हैए जिसमें बारह फीसदी की बढ़ोतरी बतायी जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में बेहतर होने की उम्मीद है। इसकी एक वजह यह है कि देश के कई भागों में समय से पहले मानसून की आमद हुई है। पहले आशंका जतायी जा रही थी कि अल नीनो प्रभाव व हालिया चक्रवाती तूफान की वजह से मानसून की गति बाधित हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरपूर मानसून से नई उम्मीदें जगी हैं कि खाद्यान्न उत्पादन उत्साहजनक रहेगा, जिससे निवेशकों में उत्साह पैदा हुआ है। वहीं दूसरी ओर देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बने रहने और घरेलू बाजार में तेजी के चलते रुपये को मजबूती मिली है। जिससे वह डॉलर के मुकाबले कुछ मजबूत हुआ। इन सभी सकारात्मक रुझानों के चलते ही शेयर बाजार झूमता नजर आया। वहीं हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते वित्तीय वर्ष में उनका मुनाफा बढ़कर एक लाख करोड़ से अधिक हो गया। हालांकिए सरकार इस मुनाफे के लिये अपनी नीतियों को श्रेय दे रही है, लेकिन बैंकों को अभी अपेक्षित लक्ष्यों के लिये बहुत कुछ करना बाकी है।

खासकर पीएसबी की कार्यशैली सुधारने और उन्हें निजी बैंकों की प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने की जरूरत है। पीएसबी के मुनाफे का आंकड़ा उत्साहजनक है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि कार्यशैली में गुणात्मक रूप से सुधार हो। बैंकों का माहौल कर्मचारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप बने क्योंकि पिछले दिनों में बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर गाहे.बगाहे असंतोष जाहिर करते रहे हैं। कहीं न कहीं बैंकों के कर्मचारी निजीकरण की चिंताओं और बेहतर सुविधाओं को लेकर आंदोलित रहे हैं। उनकी चिंताएं बैंकों के विलय से उत्पन्न चुनौतियों को लेकर भी रही हैं। निस्संदेह, बैंक कर्मियों व नियामक तंत्र के बीच बेहतर संवाद से असंतोष दूर होगा। ध्यान देने की बात यह भी कि बैंकों को डूबते ऋणों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिये सतर्क व्यवहार अपनाना होगा। बैंकों से जुड़े नीति.नियंताओं को इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि घटती श्रमशक्ति के चलते बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा है। तमाम सरकारी योजनाओं की राहत राशि को बैंकों के जरिये लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। निस्संदेह, इससे राहतकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है, लेकिन बैंकों पर दबाव बढ़ा है। बड़े पैमाने पर जनधन खातों का खुलना भारतीय लोकतंत्र के सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ा कदम है। जाहिर है नई चुनौतियों का मुकाबला बैंकों की कार्य.संस्कृति में बदलाव लाकर ही किया जा सकता है। जिसका प्रभाव कालांतर बैंकों की उत्पादकता पर ही पड़ेगा। निजी बैंकों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिये भी यह जरूरी है। यदि सरकार भी डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई में सख्ती दिखाये तो बैंकों की बड़ी पूंजी को बट्टे खाते में जाने से बचाया जा सकता है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुनाफे में आशातीत वृद्धि की उम्मीद लगायी जा सकती है।

बिन गुरु शिक्षा

किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था की आधारभूमि शिक्षक ही तैयार करते हैं। यदि शिक्षक ही पर्याप्त न होंगे तो शिक्षा के स्तर और नौनिहालों के भविष्य का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यह खबर चौंकाती है कि प्रगतिशील हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों के बीस फीसदी पद खाली हैं। निस्संदेहए यह आंकड़ा स्कूली शिक्षा की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है। किसी राज्य में यदि शिक्षकों के 25192 पद खाली हों तो स्थिति को बेहद चिंताजनक ही कहा जाना चाहिए। जो बताती है कि राज्य में नीति-नियंताओं की प्राथमिकताओं में शिक्षा कहां खड़ी है। बच्चे कल का भविष्य हैं, यदि उनकी बुनियाद ही खोखली रह जाएगी तो वे कैसे राष्ट्र का दायित्व कंधों पर उठा पाने में सक्षम होंगे। विडंबना यह भी है कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों में कम आय वर्ग के लोगों के बच्चे परिस्थितिवश ही जाते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल जिस तरह कारोबार का जरिया बन चुके हैं, उसके मद्देनजर कम आय वर्ग के अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं। दरअसल, आज जो निजी स्कूलों का कारोबार फल-फूल रहा है उसके मूल में सरकारी स्कूलों की दशा.दिशा ही है।

कुछ लोगों को लगता है कि ये स्कूल बीमार भविष्य का कारखाना बनने की दिशा में अग्रसर हैं। दरअसल, शिक्षकों की कमी से वे स्कूल जूझ रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। यह भी विडंबना है कि येन.केन.प्रकारेण नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों की हर संभव कोशिश होती है कि उन्हें आराम की जगह में नियुक्ति मिल जाये। दरअसल, नियुक्तियां तो ग्रामीण स्कूलों के लिये होती हैं, लेकिन शिक्षक किसी न किसी तरह तबादला शहरी स्कूलों में करवा लेते हैं। बहरहाल, तंत्र को इस गंभीर होती समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता बनाना चाहिए।

दरअसल, नीति नियंताओं को समझना चाहिए कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तदर्थवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। स्थायी शिक्षकों की जरूरत को न तो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से पूरा किया जा सकता है और न ही अनुबंध पर की गई शिक्षकों की नियुक्ति से। सत्ताधीशों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि राज्य के सबसे पिछड़े जनपद नूंह में क्यों शिक्षकों के 4353 पद खाली हैं। जाहिर जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। स्कूल नहीं जाएंगे तो जाहिर है परिपक्व व जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगे। शिक्षा एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है। पढ़े.लिखे व्यक्ति की सोच व जीवनशैली में अनपढ़ व्यक्ति के मुकाबले खासा गुणात्मक बदलाव होता है। ऐसे वक्त में जब देश के विभिन्न राज्यों में तमाम तरह के लोकलुभावन अभियान चलाये जा रहे हैं, राज्य सरकार को भी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चलाना चाहिए। इससे जहां एक ओर सरकारी स्कूलों के बच्चों के भविष्य को संवारा जा सकेगा, वहीं तमाम पढ़े-लिखे बेरोजगारों की हताशा दूर होगी। वह भी तब जब राज्य में बेरोजगारी की दर काफी ऊंची बतायी जाती है। शिक्षकों की भर्ती का अभियान चलाकर राज्य सरकार राजनीतिक लाभ भी ले सकती है और छात्रों व बेरोजगारों का भविष्य भी संवार सकती है।

इसके अलावा भी सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जिससे छात्र-छात्राएं मौजूदा समय के साथ कदमताल कर सकें। उन्हें कार्य कौशल विषयक शिक्षा मिले। साथ ही नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को भी हासिल करने के लिये पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति अपरिहार्य ही है। सत्ताधीश इस तथ्य को स्वीकारें कि शिक्षकों की कमी के चलते ही राज्य की परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन खराब रहता है। जिसकी वजह से अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने में भलाई समझते हैं। विद्यार्थियों, खासकर लड़कियों, द्वारा पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को भी इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। निस्संदेह बेहतर और संपूर्ण शिक्षा हासिल करना हर छात्र का अधिकार है, इस दिशा में सरकार से गंभीर पहल की उम्मीद की जानी चाहिए। सरकार को अपनी रोजगार नीति की भी समीक्षा करनी चाहिए।

फिजूलखर्ची पर फटकार

यह विडंबना ही है कि जनता के हितों की दुहाई देकर सत्ता में आने पर राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वे दावे तो आसमान से तारे तोड़ लाने के करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत निराशाजनक ही होती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि थोड़े से काम को इस तरह प्रचारित किया जाता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। जबकि हकीकत में जनता के करों से अर्जित धन को निर्ममता से प्रचार-प्रसार में उड़ाया जाता है। विकास की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करके सरकारी धन को विज्ञापनों व फिजूलखर्ची में उड़ाने वाली दिल्ली सरकार की कारगुजारियों पर शीर्ष अदालत की फटकार को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अदालत ने सख्त लहजे में कहा भी कि ऐसा क्यों है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है? तो फिर विज्ञापनों पर अनाप.शनाप खर्च होने वाला धन कहां से आ रहा है? दरअसल, दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद रैपिड रेल परियोजना के लिये आर्थिक योगदान देने में वित्तीय संकट का रोना रोया था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जनहित की योजनाओं में योगदान करने से कतराने वाली सरकार विज्ञापनों तथा अन्य गैर जरूरी काम के लिये धन कहां से ला रही है? यही वजह है कि दिल्ली सरकार की नीयत को भांपते हुए शीर्ष अदालत ने विज्ञापनों पर खर्च किये गये उस धन का विवरण मांगा है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में व्यय किया गया। जानकार सूत्र बता रहे हैं कि जिस रैपिड रेल परियोजना में दिल्ली सरकार ने योगदान देने से मना किया था वह दिल्ली को राजस्थान व हरियाणा से जोड़ सकती है। जिससे सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती थी। विडंबना यह है कि सूचना अधिकार कानून के तहत हासिल जानकारी बता रही है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापनों पर किया खर्च पांच सौ करोड़ रुपये के करीब हो गया है। निश्चय ही यह लोकतंत्र में जनधन के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। शर्मनाक ढंग से गैर उत्पादक कार्यों में अंधाधुंध पैसा लुटाया जा रहा है।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जनता को सब्जबाग दिखाकर व मुफ्त का प्रलोभन देकर सत्ता में आये राजनीतिक दलों का वास्तविक चरित्र क्या है? ऐसे दलों की कथनी और करनी की वास्तविकता क्या है? अंधाधुंध विज्ञापनों पर खर्च करके राजनीतिक दल क्या हासिल करना चाहते है? क्या यह प्रचार की भूख है या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का असफल प्रयास? दिल्ली की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं कि उसे याद न हो कि दिल्ली में वोट मांगते समय आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सरकारों की फिजूलखर्ची और राजनीतिक दलों के थोथे प्रचार पर जनधन खर्च करने पर सवाल उठाये थे। जनता ने आप के दावों पर भरोसा भी किया और अपार जनसमर्थन भी दिया। मगर परिणाम वही ढाक के तीन पात रहे। दरअसल जब से आम आदमी पार्टी खुद सत्ता में आई तो राज्य सरकार की रीतियां.नीतियां पुरानी सरकारों के ढर्रे पर चल निकली हैं।

निस्संदेह यह स्थिति देश के राजनेताओं के कथनी.करनी के अंतर को भी दर्शाती है। वहीं इस प्रकरण से जनता की उस धारणा को भी बल मिला है कि सत्ता में आने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों का चरित्र एक जैसा ही हो जाता है। यदि पिछले कुछ समय में चुनावों के दौरान मतदान के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है तो उसका एक बड़ा कारण राजनेताओं की कथनी.करनी का अंतर भी है। कमोबेश पूरे देश में ही जनता में सरकारों के प्रति मोहभंग जैसी स्थिति है। लोग अब राजनेताओं की सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इस दिशा में शीर्ष अदालत की सचेतक भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। निस्संदेह, इससे जनधन के दुरुपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकेगी। अब देखना होगा कि दिल्ली की आम आदमी सरकार शीर्ष अदालत के सामने क्या बयां करती है।

तबाही की बारिश

उत्तर भारत समेत देश के अन्य भागों में अप्रत्याशित रूप से लगातार होती बारिश ने हा.हाकार मचाया है। बरसात के मौसम में बारिश और जलधाराओं में उफान आना सामान्य बात है। लेकिन इस बार की अतिवृष्टि ने बताया है कि मनुष्य शक्तिशाली होने का भले ही दंभ भरता रहे लेकिन कुदरत के रौद्र के सामने वह बौना ही है। जगह.जगह बादल फटने, नदियों में बाढ़, पानी रोकने में नाकाम बांध और भूस्खलन की घटनाओं ने लोगों में भय पैदा किया है। देश का जनजीवन अस्त.व्यस्त हुआ है। पुलों के टूटनेए बस्तियों में नौका चलाने, मकानों के भरभरा कर गिरने व कारों के बहने के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को दहशत से भर रहे हैं। कारोबार ठप हैंए स्कूल.कालेज बंद कर दिये गये हैं। फिर भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कई राज्यों में रेड, ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचाया है। करीब तीन.चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। हिमाचल में बाढ, बादल फटने, जलधाराओं में उफान व भूस्खलन में सत्रह लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। जलधाराओं में उफान से नदियों के किनारे स्थित सड़कों, मकानों, होटलों व हाईवे को नुकसान पहुंचना स्वाभाविक है। हिमाचल व उत्तराखंड में सैकड़ों सड़कें तबाह हुई हैं। विद्युत व्यवस्था ठप होने और यातायात बाधित होने की भी खबरें हैं। हिमाचल में रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब आदि नदियों में उफान से संकट गहरा हो रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज में जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने से करीब दो लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में युद्ध स्तर पर बचाव के प्रयास किये जाने की जरूरत है। अभी भी रुक.रुक कर होने वाली बारिश को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

निस्संदेह, आज पूरी दुनिया में मौसम के चरम से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मौसम की तल्खी को देखकर लगता है कि प्रकृति के खिलाफ मानव की क्रूरता का कुदरत बदला ले रही है। जलधाराओं के मार्ग में लगातार बढ़ते अतिक्रमण ने नदियों के प्रवाह को आक्रामक बना दिया है। पहाड़ हमारी जरूरत हैंए हमारी प्राणवायु के संरक्षक हैं लेकिन वे सिर्फ इंसानी विलासिता और सैर.सपाटे के स्थान नहीं हैं। वे बड़ी विकास परियोजना व बड़े बांधों का बोझ उठाने लायक भी नहीं हैं। कहा जाता है कि बड़े बांधों के इलाकों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ती हैं। इंसान ने विकास व पर्यटन तथा बस्तियों का जितना बोझ पहाड़ों पर लाद दिया है, वो इनकी क्षमता से अधिक है। पहाड़ों में विकास का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्य होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देश के महानगर व शहर अनियोजित विकास का त्रास झेल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बारिश के पानी के जो परंपरागत रास्ते थे, उन पर कब्जा करके हमने कंक्रीट के जंगल उगा दिये हैं। दूसरी ओर इस तरह की अतिवृष्टि आधारभूत ढांचे की पोल भी खोलती है। बड़े शहरों में सड़कों में जलभराव, रेलवे लाइन का पानी में डूबना व अंडरपास का जलमग्न होना अनियोजित विकास का ही परिणाम है। बारिश में हमारे आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता सामने आ जाती है। जिसके चलते सड़कों के धंसने और ट्रैफिक जाम की घटनाएं बारिश में सामने आती हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस मानसून का हम पलक.पांवड़े बिछा कर स्वागत करते थे, जो बारिश कभी आनंद का प्रतीक होती थी, वह अब डराने क्यों लगी हैं। कहीं न कहीं हमारे नगर नियोजक, प्रशासक, इंजीनियर व नीति नियंता भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने में विफल रहे हैं। जाहिर बात है, यदि आधारभूत ढांचे का निर्माण पर्याप्त योजना व दूरदर्शी सोच के अभाव में किया जाएगाए तो अतिवृष्टि से लोगों का मुश्किलों में फंसना स्वाभाविक ही है।

लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य : श्री हरिचंदन

रायपुर (प्रमोदन)। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन अपने तीन दिवसीय ओडिशा प्रवास के दौरान ओडिशा के पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय प्रदीप किशोर दास के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह भुवनेश्वर के गीतगोबिंद सदन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदीप किशोर दास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ समाज के लिए किये गये योगदान को याद किया और स्वर्गीय दास को एक ईमानदार नेता बताया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री हरिचंदन ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भ्रष्टाचार से मुक्त एक स्वस्थ एवं सुंदर देश का निर्माण करने के लिए में प्रत्येक नागरिक को योगदान देना चाहिए। योग्य लोगों को ही राज्य एवं देश पर शासन करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की आवश्कता है। स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता का अधिकार है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सभी को भागीदारी करने का अनुरोध किया।

विश्राम गृह बनने से आश्रय की बेहतर सुविधा मिल सकेगी : ताम्रध्वज साहू

ग्राम नगपुरा में विश्राम गृह भवन का हुआ लोर्कापण

दुर्ग (प्रमोदन)। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अन्तर्गत ग्राम नगपुरा में विश्राम गृह भवन का लोर्कापण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने उद्बोधन में कहा की विश्राम गृह भवन बनने से आश्रय की बेहतर सुविधा मिल सकेगी और जनता को बैठकों के आयोजन हेतु इसका लाभ मिलेगा।

दुर्ग ग्रामीण विधासनभा की जनता को शासन की लाभदायक योजनाओं का लाभ और विकास कार्यों की सौगात देकर समृद्ध एवं सक्षम बनाया जा रहा है। नवीन विश्राम गृह भवन लगभग 80 लाख की राशि से बनाया गया है। इस भवन में 03 विश्राम कक्ष, एक डायनिग हाल, एक किचन शेड एएवं 50 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला एक सभाकक्ष बनाया गया है।

शिव की वाणी शिवानी दीदी का 22 जुलाई को भिलाई आगमन

भिलाई (प्रमोदन)। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयएराजयोग भवनएभिलाई में मीडिया परिचर्चा-स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन 9 जुलाई रविवार के दिन किया गया। इस कार्यक्रम में भिलाई के पत्रकारों के साथ रायपुर से आई पत्रकार प्रियंका कौशल भी शामिल हुई। प्रियंका कौशल ने ब्रह्माकुमारिज़ संस्था की दीदियों की अथक सेवाओं के बारे में बताते हुए कहा कि ब्रह्माकुमारी आशा दीदी भिलाई के सेवाकेंद्रो की निदेशिका के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान को मिलकर बने इंदौर जोन की कार्यभार संभल रही मुख्य दीदियों में से एक है। उन्होंने अपने राजयोग मेडिटेशन के अनुभवों को भी साझा कियाण्कार्यक्रम के दौरान सभी मीडिया सदस्यों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका ब्रह्माकुमारी आशा दीदी ने आध्यात्म जगत की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता शिवानी बहन के भिलाई आगमन की जानकारी देते हुए बताया कि शिवानी बहन ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद भी शनिवार 22 जुलाई को भिलाई के लिए समय दिया है तथा गॉड्स पावर मेरे पास अर्थात् परमात्मा शक्तियां हर एक के जीवन में धारण हो, विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगी। कार्यक्रम शनिवार 22 जुलाई को बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंडएसेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 7 में संध्या 6.30 बजे से आयोजित होगा। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए विशाल डोम का निर्माण करवाया जा रहा है।

बोरसी भाठा तालाब को संरक्षित और गन्दगी मुक्त बनाने में विधायक, महापौर के साथ-साथ पार्षद, स्थानीय रहवासी भी सहभागी बनें

दुर्ग (प्रमोदन)। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 50 बोरसी भाठा स्थित तालाब का पुराने व परंपरागत जलस्रोतों की सफाई के लिए नगर पालिक निगम द्वारा श्रमदान महाअभियान चलाया गया। विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा निगम सफाई कर्मी के साथ साथ स्थानीय पार्षद श्रमदान करने अल सुबह बोरसी भाठा तालाब पहुँचे। उन्होंने इसकी शुरुआत वार्ड पार्षद ज्ञानदास बंजारे, निगम सफाई कर्मी, आम नागरिकों के साथ-साथ और मानव साख समिति के सदस्य के साथ सफाई अभियान अमला की उपस्थिति में किया गया। सुबह से चलने वाले श्रमदान अभियान से जुड़ने विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और स्थानीय पार्षद ज्ञानदास बंजारे, एल्डरमेन राजेश शर्मा, स्थानीय, समाजसेवी संगठन, मानव साख समिति के सदस्य व वार्ड नगरिक स्वस्फूर्त सामने आये। इस दौरान विधायक अरुण वोरा ने इस अभियान की काफी सराहना की। कहा कल के लिए जलश् बचाना समय की मांग है। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि जलस्रोतों की श्रमदान से सफाई किए जाने से बरसाती पानी के संग्रहण में जहां सहायता मिलेगी। वहीं जल संरक्षण और जलस्रोतों में गंदगी रोकने के लिए आम नागरिक जागरूक होंगे। तालाब को गंदगी से बचाने का आग्रह, विधायक व पार्षद,मानव साख समिति के सदस्य और स्थानीय श्रमदान करने सुबह बोरसी भाठा तालाब पहुंचकर चारो तरह सफाई की। इस अभियान पर महापौर धीरज बाकलीवाल और आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने आसपास के रहवासियों से आग्रह किया कि तालाब को गंदगी से बचाएं। जलस्रोत के इस तरह दूषित होने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। भीषण जलसंकट की स्थिति को रोकने निस्तारी के लिए उपयोग होने वाले इन तालाबों को संरक्षित करने की जरूरत है। विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने श्रमदान अभियान के लिए पहल को अनुकरणीय बताते हुए अपने-अपने क्षेत्र में नागरिकों को इससे प्रेरणा लेकर तालाब, कुएं और बावड़ी आदि की श्रमदान से सफाई करने आगे आने की बात कही।

अमलोर हाईस्कूल के शिक्षक एवं छात्राओं ने मुख्यमंत्री हाउस का किया घेराव

रायपुर (प्रमोदन)। अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ महासमुंद क्षेत्र के अमलोर हाई स्कूल के बच्चे ब्ड हाउस पहुंचे। कॉपी.किताब और बैग को सीएम हाउस के गेट पर रखकर बच्चे हाई स्कूल में शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल में बच्चों को एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। बच्चों के साथ में ग्रामीणथ भी मौजूद हैं। शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की बच्चे मांग कर रहे हैं। यह मामला महासमुंद जिले के शिवपुर ब्लाक में अम्लोर गांव है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों को आश्वासन दिया है। आज शाम तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। जिसके बाद बच्चे महासमुंद वापस लौट गए हैं। जानकारी के अनुसार महासमुंद जिले के शिवपुर ब्लाक में अम्लोर गांव के कुछ ग्रामीण और स्कूली बच्चे आज सुबह.सुबह रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। उन्होंने सीएम हाउस के सामने अपने कॉपी पुस्तक रखकर शिक्षक की मांग की। बता दें कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते है वहां सिर्फ एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। तमाम स्कूलों में बच्चों के बैठने से लेकर पेयजल तक की व्यवस्था तक नहीं हैं। यहां तक की एक स्कूल महज शिक्षामित्र के सहारे चल रहा है। नहीं तो एक ही शिक्षक के सहारे पूरे स्कूल की व्यवस्था टिकी है।

आयुक्त रोहित व्यास ने निर्माणाधीन आवासों का किया निरीक्षण

एजेंसी को निर्माण कार्य पूर्ण कर शीघ्र निगम को हैंड वर्क करने के दिए निर्देश

भिलाई (प्रमोदन)। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश एजेंसी को दिए हैं। आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का निरीक्षण कर जायजा लिया। आयुक्त ने खमरिया, सूर्या विहार के पीछे, कृष्णा इंजरिंग कॉलेज के पीछे आदि के आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि शीघ्र अति शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर मकान मोर आस, मोर मकान मोर चिन्हारी के सभी आवासों को ब्लॉक वाइज पूर्ण करें ताकि प्रतीक्षारत लोगों को आवास आबंटित करने की कार्रवाई की जा सके तथा लोगों को आवास का फायदा मिल सके। आयुक्त ने आवास निर्माण के कार्यों को लेकर गुणवत्ता बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बाहरी विद्युतीकरण के लिए विद्युत विभाग से समन्वय बनाकर विद्युतीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि भीतर में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है।

गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर आवास आवंटन की प्रक्रिया में शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है। लोगों को आवास का लाभ देने के लिए आवास से संबंधित कार्यों को त्वरित तौर पर किया जा रहा है। आयुक्त ने निरीक्षण में निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, इससे संबंधित सभी कार्य समय पर पूर्ण करें। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता डीके वर्मा, उप अभियंता दीपक देवांगन, कार्यरत एजेंसी रवि शंकर त्रिपाठी एवं विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा ओटेबंद में सेंधमारी, चैनल गेट उखाड़ कर घुसे चोर

अंडा (प्रमोदन)। गुंडरदेही ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे ग्राम ओटेबंद में विष्णु धाम मंदिर परिसर के पास ही संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में बीती रात को अज्ञात चोरों ने पैसे चुराने का प्रयास किया, हालांकि चोर कामयाब नहीं हुए। लेकिन बैंक के चैनल गेट को नीचे से उखाड़ कर अंदर घुसे थे। फिर लॉकर तक पहुंचते हुए लाकर को भी तोड़ने का प्रयास किए लेकिन असफल रहे। लॉकर का हैंडल टूटने के बाद चोर वहां से कैमरे का डीवीआर निकाल कर ले गए, नकदी चुरा नहीं पाए लेकिन पकड़े जाने के डर से कैमरे से संबंधित सामान उठाकर ले गए। घटना के मामले में स्पेशल स्क्वाड टीम और स्थानीय थाना की पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। गुण्डरदेही थाना प्रभारी वीना यादव का कहना है कि अभी जांच चल रही है। जल्द आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम सांकरा की ग्रामीण युवा-युवतियां रीपा में कर रही स्टेशनरी सामग्री बनाने का काम

▸▸ स्थानीय बाजार के साथ ही सरकारी कार्यालयों से मिल रहे सामग्री के आर्डर

बेमेतरा (प्रमोदन)। यह अच्छी खबर है कि ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवा.युवतियां महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में स्टेशनरी सामग्री बनाने का काम कर रही है। बेमेतरा जिले के विकासखंड के ग्राम सांकरा में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) में स्टेशनरी.प्रिंट यूनिट स्थापित की गयी है। स्थानीय युवा.युवतियों को रोजगार मिला है। युवा विकास समिति ग्राम सांकरा के 10 युवा.युवतियां इस काम में जुटी हुई हैं। समिति सचिव कुमारी देवमति साहू ने बताया कि पड़ौसी जिला दुर्ग से कच्चा माल ला कर विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी सामान जैसे कॉपी, रजिस्टर, डायरी, फाईल, पम्पलेट इत्यादि तैयार कर सरकारी और ग़ैर सरकारी कार्यालयों, स्कूल शाला आश्रमों में मांग अनुसार मुहैया करा रहे है। उन्होने बताया कि वर्तमान में जनपद पंचायत बेरला से माप पुस्तिका, फाईल कव्हर, फाईल पेड, रजिस्टर के पांच हजार नग का ऑर्डर मिला है वहीं शिक्षा कार्यालय बेरला से भी 250 नग रजिस्टर के साथ ही फाईल कव्हर, फाईल पेड सहित अन्य सामग्री लगभग 500 नग ऑर्डर मिला है।

समिति के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि चूंकि हाल ही में यह कार्य शुरु किया गया है, जिसकी मार्केटिंग भी अभी उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। अभी स्थानीय बाजार एवं कार्यालयों में इसकी जानकारी दी जा रही है जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसी योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करना और सामाजिक उत्थान के लिए भी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर व सामर्थ्यशाली बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं।

समिति के सदस्यों का कहना है कि ऐसी नवीनतम योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। वे इसके लिए शासन को धन्यवाद देते है। समिति सदस्य भुनेश्वरी, आंचल रात्रे, भगवती साहू ने रीपा योजना की प्रशंसा और सरकार के प्रति आभार प्रदर्शित करती हैं, जो नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इसके जरिए से, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा.युवतियों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम योजनाएं न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करते हैंए बल्कि उनके माध्यम से समाज का विकास भी होता है। ग्रामीण युवा.युवतियों को नए कौशल सीखने और उन्नति करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी जीविका मानसिकता और आत्मविश्वास में सुधार होता है। इस तरह के कार्यों से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि वे भी सामाजिक उत्थान के लिए अपने सामर्थ्य और कौशल का उपयोग कर सकते हैं। कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने ज़िला अधिकारियों को जरूरत के अनुसार स्टेशनरी सामग्री यहीं से ख़रीदने के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा अधिकारी व आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के अधिकारी को स्कूल, शाला.आश्रमों के बच्चों के लिए भी कॉपी, रजिस्टर आदि स्टेशनरी सामग्री क्रय करने को कहा हैं।

बारिश का कहर

हिमाचल में लैंडस्लाइड, जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा; यमुना खतरे के निशान के ऊपर

नई दिल्ली। उत्तर भारत में भारी बारिश ने इस क्षेत्र को घुटनों पर ला दिया है, जिससे पिछले तीन दिनों में 37 से अधिक लोगों की जान चली गई है। दिल्ली की यमुना नदी में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, हरियाणा के करनाल के कई गांवों में गंभीर जल-जमाव हो गया है और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंडी, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए अचानक बाढ़ की चेतावनी भी दी है। वहीं देश के चार राज्यों में एनडीआरएफ की 39 टीमों को तैनात किया गया है।

बताते चलें कि चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से लेकर कुल्लू तक जगह-जगह लैंडस्लाइड हुई है। हाइवे अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सैकड़ों गाड़ियां कुल्लू और मनाली में फंसी हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हाईवे को खोलने में 48 घंटे लगेंगे।

वहीं पंजाब और हरियाणा में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में दो दिनों के भीतर 9 लोगों की मौत हुई। सेना ने भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के बाद पंजाब की एक यूनिवर्सिटी से 960 लोगों को बचाया है। हरियाणा की बात करें तो यहां के अंबाला जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और घग्गर नदी उफान पर है। शालीमार कॉलोनी, हीरा नगर, अशोक विहार और कई अन्य आवासीय कॉलोनियों में पानी भर गया। बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। इस वक्त यमुना का जलस्तर 206.24 मीटर है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। यमुना के निचले इलाकों में रहने वालों को हिदायत दी गई है कि वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। 206 मीटर के स्तर को पार करते ही यमुना के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू हो जाता है। उत्तराखंड में आफत की बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि जोशीमठ में ग्लेशियर टूट गया है। जिसके चलते जोशीमठ और उसके आसपास के गांवों के डूबने की आशंका है। ग्लेशियर के टूटने से लगातार पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है।

विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में हुआ बड़ा विस्तार

जयपुर। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार करते हुए 48 महासचिव, 21 उपाध्यक्ष, 121 सचिव एवं 25 जिलाध्यक्ष बनाये गये है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे की अनुशंसा के बाद प्रदश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी एवं राजथान में पार्टी के शेष रहे जिला अध्यक्षों की सोमवार को सूची जारी की। सूची के अनुसार इस कार्यकारिणी विस्तार में स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के भाई गोपाल कृष्ण को महासचिव बनाया गया हैं वहीं लंबे समय बाद नियुक्त किए गए 25 जिलाध्यक्षों में विधायक गोपाल मीणा एक मात्र विधायक है जिन्हें इनमें शामिल किया गया हैं और श्री मीणा को जयपुर ग्रामीण में जमवारामगढ़ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल को अपने पद पर बरकरार रखा है जबकि 21 उपाध्यक्ष बनाये गये हैं उनमें डॉ जितेंद्र सिंह, नसीम अख्तर इंसाफ, गजराज खटाना, हाकम अली खान, घनश्याम मेहर, भरतराम मेघवाल, जगदीश चंद्र जांगिड़, मंजू मेघवाल, वीरेंद्र बेनीवाल, हीरालाल दरांगी, हंगामी लाल मेवाड़ा , कैलाश मीणा, रतन देवासी, रामविलास चौधरी, रमेश खंडेलवाल, सुशील शर्मा, जगतार सिंह कंग , समरजीतसिंह , रफीक मांडलिया, राजकुमार जयपाल एवं दर्शन सिंह शामिल है। इसी तरह श्री ललित तुनवाल को महासचिव (संगठन) बनाया गया हैं जबकि बनाये गए 48 महासचिवों में प्रशांत बैरवा, राकेश पारीक, रीटा चौधरी ,जियाउर रहमान, जसवंत गुर्जर, आर सी चौधरी , स्वर्णिम चतुर्वेदी, विशाल जांगिड़, देशराज मीणा, फूल सिंह ओला।

बारिश के बाद चमकी धूप; नेशनल हाईवे खुला, गृह मंत्री अनिल विज ने नाव से किया अंबाला का दौरा

हालांकि लोगों को पेयजल की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है

अंबाला । अंबाला में तीन दिनों से हो रही बारिश के बाद मंगलवार का दिन कुछ राहत भरा रहा है। सुबह धूप निकल आई और आसमान साफ हो गया। जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, जिन राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर दिया गया था उन्हें भी सुबह खोल दिया गया। जिससे दिल्ली और पंजाब जाने वाले लोगों को राहत मिली।

दूसरी ओर अंबाला छावनी और अंबाला शहर दोनों में अभी तक जलभराव जस का तस है। यहां पर पानी की निकासी का रास्ता नहीं बन पा रहा है। जिसके कारण पानी घट नहीं रहा है। हालांकि लोग अब अपने सामान को सुरक्षित रूप से पानी में से बाहर निकालकर ला रहे हैं। इसके साथ ही अंबाला छावनी में गृहमंत्री अनिल विज ने नाव के बैठक अघोषित बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का जाएजा लेने पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। रात्रिभर सेना का रेस्क्यू अभियान टांगरी नदी के तटीय इलाकों में चलता रहा। यहां पर सेना ने करीब 200 लोगों को सुरक्षित अपने घरों से निकाला। सेना की टुकड़ी एक तरफ से लोगों की भीड़ का प्रबंधन कर रही थी तो दूसरी तरफ धीमे-धीमे बोट से लोगों के घर तक पहुंचकर उन्हें निकाल रही थी। रिहायशी कॉलोनियों में अभी भी लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। जिससे सुबह से लोग निकालने में जुट गए। इसके साथ ही दो दिन से लाईट नहीं थी मगर अब स्थिति ठीक है।

किम जोंग-उन की बहन की अमेरिका को चेतावनी, अवैध घुसपैठ पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

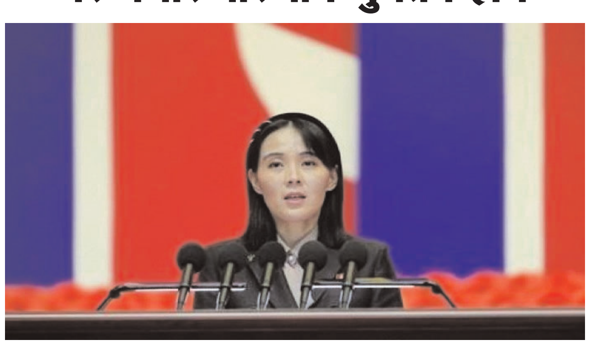

सोल । उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग ने मंगलवार को चेतावनी दी कि प्योंगयांग के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बार-बार अवैध घुसपैठ की स्थिति में जासूसी विमानों को बहुत गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दी। किम यो-जोंग ने कहा, मैंने सेना की जवाबी कार्रवाई के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। बार-बार अवैध घुसपैठ की स्थिति में, अमेरिकी सेना को बहुत गंभीर परिणाम भुगतना होगा। यह चेतावनी बीती देर रात एक बयान जारी करने के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक अमेरिकी जासूसी विमान दिन में उत्तर कोरिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इससे पहले सोमवार को उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी अमेरिकी जासूसी विमानों पर हाल ही में उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप लगाया था और धमकी दी थी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे विमानों को मार गिराया नहीं जाएगा।

शादी पूर्व संबंधों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था प्रेमी, महिला ने दो भाइयों के साथ मिलकर दिया खौफनाक वारदात

रांची। झारखंड के पलामू में एक महिला एवं उसके दो भाइयों ने मिलकर एक 19 वर्षीय युवक की हत्या कर दी और शव को जंगल में दफना दिया। महिला का कहना है कि युवक विवाह पूर्व संबंधों को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था।

पुलिस ने लगभग 15 दिनों बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया है। मंगलवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में युवक के शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मारे गए युवक का नाम नयन कुमार सिंह है। वह पलामू के छतरपुर का रहने वाला था। बीते 22 जून से वह अचानक घर से लापता हो गया। घरवालों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नयन का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। सूचना के आधार पर पुलिस युवती के पाटन थाना अंतर्गत बरसैयता गांव पहुंची। पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है और वह छत्तीसगढ़ में रहती है। पुलिस ने संदेह के आधार पर युवती के ससुराल जाकर उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

आखिरकार वह पुलिस के सामने टूट गई और इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। उसने बताया कि शादी के पहले नयन के साथ उसके संबंध थे। शादी के बाद भी वह उसे पुराने संबंधों के आधार पर ब्लैकमेल कर रहा था। कुछ दिन पहले वह अपने मायके आई तो नयन उससे मिलने आ पहुंचा। उसने अपने दोनों भाइयों को इसकी जानकारी दी। फिर तीनों ने मिलकर उसकी हत्या का प्लान

सिंगापुर में पुलिसकर्मी पर हमला करने पर भारतीय मूल के व्यक्ति को दस साल की जेल

सिंगापुर। 25 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 2020 में छापेमारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी को मुक्का मारने और लात मारने के लिए 10 साल से अधिक की जेल की सजा और 4,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। निखिल एम. दुर्गुडे को पिछले महीने आठ आरोपों में दोषी ठहराया था। इसमें एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना, भांग रखना और मेथामफेटामाइन का सेवन करना शामिल है। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सजा सुनाए जाने के दौरान 15 अन्य आरोपों पर विचार किया गया। जिला अदालत की न्यायाधीश जसवेंद्र कौर ने कहा कि हमले के दौरान निखिल ने पुलिस अधिकारी का अपमान भी किया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, वरिष्ठ स्टाफ सार्जेंट चुआ मिंग चेंग और इंस्पेक्टर झेंग यियांग सहित तीन अधिकारी 5 नवंबर, 2020 को एक पुलिस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में बालेस्टियर में सिटी सूट्स की एक इकाई में गए थे। उन्होंने खुद को निखिल और उसके साथियों, प्रकाश मथिवनन और मलानी नायडू प्रभाकर को पुलिस के रूप में बताया।

आतंकी साजिश मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कश्मीर में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

कश्मीर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को आतंकी साजिश मामले में दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने ये रेड जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकी संगठनों की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए की थी। बता दें कि मई में एनआईए ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के बडगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग जिलों में 13 स्थानों की तलाशी ली थी।

एनआईए के अनुसार, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और छोटे हथियारों के साथ जम्मू-कश्मीर में हिंसक आतंकवादी हमले करने की योजना बनाई थी। एजेंसी ने पहले कहा था कि ये योजनाएं इन आतंकवादी संगठनों की ओर से स्थानीय युवाओं और ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के साजिश का हिस्सा थीं।

अधिकारियों के मुताबिक, पिछले साल एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए आतंक से संबंधित मामले के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। आंतकी गिरोह का भंडाफोड़ करने और उनके आतंकी मनसूबों को नाकाम करने के लिए कार्रवाई जारी है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पाकिस्तान से सक्रिय संदिग्ध आतंकवादियों के घरों पर छापेमारी की। सूत्रों ने आगे बताया कि छापेमारी किश्तवाड़ जिले की छतरू तहसील के राहलथल गांव में की गई।

पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से उन संदिग्ध आतंकवादियों के घरों पर छापेमारी की जा रही है, जो किश्तवाड़ से पाकिस्तान भाग गए हैं और वहां से काम कर रहे हैं।

31 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

पूजा स्थल अधिनियम : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया और समय

नई दिल्ली । पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। मामले के दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र को 31 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वृंदा ग्रोवर ने अदालत से कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने का आग्रह किया। ग्रोवर ने कहा, स्थगन की मांग करने वाला एक अंतरिम आवेदन है। देश भर में अधिनियम लागू होने के दौरान मामलों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आज की स्थिति के अनुसार, अधिनियम लागू है। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह विवादित धार्मिक स्थलों के संबंध में देश भर की विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों और कानूनी कार्यवाही पर पूर्ण रोक लगाने के लिए अधिनियम का उपयोग नहीं कर सकती है। पीठ ने कहा कि किसी विशिष्ट मामले में शामिल प्रत्येक पक्ष को व्यक्तिगत रूप से संबंधित अदालत से स्थगन का अनुरोध करना चाहिए, अधिनियम के अस्तित्व पर प्रकाश डालना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि इस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाई गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र इस मामले में स्थगन मांगने की प्रवृत्ति दिखा रहा है, और इसे अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस साल जनवरी में, शीर्ष अदालत ने अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय बढ़ा दिया था। इसने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए फरवरी 2023 के अंत तक का समय दिया।

पिछले साल 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए 12 दिसंबर तक का समय दिया था। 21 अक्टूबर को, पीठ ने केंद्र को 31 अक्टूबर या उससे पहले एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पास हेलिकॉप्टर क्रैश, सवार सभी 6 यात्रियों की मौत

काठमांडू। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में पांच नागरिक मैक्सिको के थे। खबर है कि खोज अभियान में सभी 6 शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल, मैक्सिको ने नागरिकों की पहचान को उजागर नहीं किया गया है। हेलीकॉप्टर में कैप्टन चेत बहादुर गुरंग भी सवार थे। नेपाल के मनांग एयर का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह सोलुखुम्बु जिले के लिखुपिके ग्रामीण नगर पालिका के लमजुरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भुल ने बताया कि सोलुखुम्बु से काठमांडू की ओर जा रहे हेलीकॉप्टर का सुबह 10 बजे कंट्रोल टॉवर से संपर्क टूट गया था। बाद में वह जिरी और फाप्लू के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ग्रामीण नगर पालिका के उपाध्यक्ष न्वांग लखपा शेरपा के अनुसार स्थानीय लोगों ने हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी दी थी। हेलीकॉप्टर भकान्जे गांव के लमजुरा के चिहंदांडा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कोशी प्रांत पुलिस के डीआइजी राजेशनाथ बस्तोला के मुताबिक सभी शव बरामद कर लिए गए हैं।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जेएलएन अस्पताल में 'जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा' मना

भिलाई (प्रमोदन)। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर-9 स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवांए) डॉ एम रविन्द्रनाथ के मार्गदर्शन में 11 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक 'जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा' शुरू किया गया। ज्ञात हो कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस अवसर पर बीएसपी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अधोलिखित मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद बिनायके, डॉ. विनीता द्विवेदी, डॉ. राजीव पाल और डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर उपस्थित थे। साथ ही अस्पताल के विभिन्न विभागों से डॉक्टर नर्सिंग और पैरा-मेडिकल स्टाफ भी भी उपस्थित थे। जिसका उद्देश्य लोगों को जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक पहलू और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक करना है।

इसी पहल के तहत जेएलएन अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के विशेष सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के इस वर्ष के नारे के अनुरूप था, 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर, आइए खुशी और समृद्धि के विकल्प के रूप में परिवार नियोजन को अपनाने का संकल्प लें।

मुख्य अतिथि डॉ. रवीन्द्रनाथ एम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का अवसर कोई उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन का दिन है। हम वर्तमान जनसंख्या को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक प्रयासों से कम से कम हम जनसंख्या को स्थिर कर सकते हैं और इसे और बढ़ने से रोक सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर भारी पड़ रहा है। डॉ. रवीन्द्रनाथ एम ने उपस्थित सभी लोगों और विशेषकर युवा पीढ़ी से अपने जीवन में परिवार नियोजन अपनाने का आग्रह किया। डॉ. प्रमोद बिनायके और डॉ. विनीता द्विवेदी ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और लोगों से परिवार नियोजन अपनाने का आग्रह किया।

विश्व जनसंख्या दिवस 2023 को जेएलएन अस्पताल में दो चरणों में मनाया जा रहा है। 27 जून से 10 जुलाई 2023 तक मोबिलाइजेशन पखवाड़ा (दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा) और 11 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा, जिसमें जनसंख्या-स्थिरीकरण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाने का आग्रह किया गया, जैसे परिवार नियोजन, गर्भ निरोधकों का उपयोग, पुरुष और महिला नसबंदी आदि। पीजी कॉलेज ऑफनर्सिंग, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई की छात्राओं द्वारा एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवांए) डॉ. शायला जेकब द्वारा दिया गया। स्वागत भाषण एसीएमओ डॉ. रोशन हुसैन ने दिया जबकि कार्यक्रम का संचालन चीफ कंसल्टेंट डॉ. हिमानी गुप्ता ने किया ।

वर्षा जल निकासी पर हमेशा नजर रखे कही पर भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिये : ईश्वर सिंह ठाकुर

जामुल (प्रमोदन)। नगर पालिका जामुल क्षेत्र में निर्माण कार्य के अतिरिक्त मुलभुत कार्यो का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसका निरीक्षण करने नपा अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर वार्ड क्रमांक 13 लवकुश नगर पहुंचे। वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रहा है। जिसको देखते हुए सफाई की विशेष व्यवस्था नपा प्रशासन द्वारा किया गया है। जामुल नपा अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि बरसात के मौसम में जल जनित बीमारियों की संभावना अधिक रहती है। जिसमें सफाई के साथ-साथ सावधानिया और बचाव कार्य भी आवश्यक है। श्री ठाकुर ने नपा प्रशासन के आधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया की वर्षा जल निकासी पर हमेशा नजर रखे कही पर भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिये क्योंकि अधिकतर रोग निकासी पानी के रूकने से होता है। जिसमें मच्छर सहित अन्य हानिकारक जीव पनपते है। जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

साथ ही यह भी ध्यान रखे कि आम रास्ता में आने जाने से लोगो को परेशानी न हो। जहां कही भी रास्ते में गढढ़ा या पानी भरा हो कच्ची नाली निकाल के पानी तुरंत खाली करें एवं मार्ग को समतल कर लोगो को सुविधा प्रदान करें। साथ ही नालियों में आवश्यक रूप से मैलाथियान, टेमीफाश या अन्य दवाईयों का छिडकाव प्रत्येक वार्डो में करे जिससे मौसमी बिमारी ना फैले। साथ ही वार्डवासियों द्वारा रोड एवं नाली निर्माण का मांग किया गया जिस पर नपा अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने आश्वस्त किया की शीघ्र ही आप लोगो के मांग के अनुरूप आपके वार्ड में रोड एवं नाली निर्माण होगा। वार्ड निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद कविता विश्वाल, हेमन्त, सफाई कर्मचारी, सुपरवाईजर वार्डवासी उपस्थित थें।

शिवनाथ नदी के सायफन की सफाई, शिवनाथ इंटरवेल की सफाई में लगा पूरा अमला

दुर्ग (प्रमोदन)। नगर पालिक निगम दुर्ग जल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से इंटरवेल के आस पास झिल्ली पन्नी एवम रेत को निरन्तर निगम अमला द्वारा निगम क्षेत्र शहर में पेयजल व्यवस्था हेतु निगम के कर्मचारी नदी के अंदर उतरकर जान जोखिम में डालकर पंप में फसे कचरा झिल्ली पन्नी की सफाई का कार्य लगातार कर रहे है। महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने अधिकारियों को निर्देश की समय समय पर गैंग लगवाकर इंटरवेल की सायफन की सफाई होती रहे। शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित न हो इसको ध्यान में रखकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है।दोनो इंटकवेल में मिट्टी के साथ जलकुंभी जमा न हो जिसके कारण 24 एवं 42 एमएलडी के इंटकवेल में सफाई के लिए एक्सपर्ट गैंग लगाया गया है।पानी की क्षमता कम न हो इसलिए सफाई कार्य लगातार जारी है। इंटकवेल के अंदर उतरकर सायफन में फंसे कचरे को सफाई किया गया। गहराई में उतर कर पम्प में फसे झिल्ली पन्नी को बड़ी मशक्कत के बाद कचरा को सफाई कर बाहर निकला गया।

भूपेश सरकार के जंगल राज को खत्म करेंगी महिलाएं : स्मिता बरूह

- ▸▸ महिला मोर्चा जिला स्तरीय बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य स्मिता बरूह की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न
- ▸▸ सैकड़ों की संया में महिलाओं ने किया भाजपा प्रवेश

दुर्ग (प्रमोदन)। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एवं महिला मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य स्मिता बरुह, जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की विशेष उपस्थिति में एवं भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दिव्या कलिहारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उषा टावरी, चंद्रिका चंद्राकर, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू, जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, मंत्री आशीष निमजे, महिला मोर्चा जिला महामंत्री गायत्री वर्मा, जय श्री राजपूत, थर्ड जेंडर समुदाय से कंचन शिंदे उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा स्मिता बरुह ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्रियाशील रहने वाली सशक्त पार्टी है और इस पार्टी के एक महत्वपूर्ण मोर्चा में से एक महिला मोर्चा है, जिसमें काम करने वाली समस्त मातृ शक्तियों को मैं नमन करती हूं। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे दुर्ग जिले का प्रवास कार्य दिया गया और कल प्रथम दिवस पर बूथ और विधानसभा स्तर की बैठकें हुई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में महिलाओं की विशाल उपस्थिति को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किए गए कार्य से महिलाएं प्रसन्न है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गंगाजल की कसम खाकर प्रदेश में शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूह की बहनों का कर्ज माफी की बातें की थी लेकिन प्रदेश की महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला और तो और प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल है, महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं, लगातार हो रही घटनाओं से यह स्पष्ट है कि यहां पर कानून राज नहीं जंगलराज चल रहा है। महिलाओं को आगामी चुनाव को लेकर कमर कसकर तैयार रहना है और भाजपा की विजय पताका फहरानी है । इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का भाजपा में प्रवेश को देखते हुए पूरा विश्वास दिलाया ।

चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका एक सूत्रीय मांग को लेकर दिया धरना

दुर्ग (प्रमोदन)। चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वालंटियर की, एक सूत्रीय मांग- कलेक्टर दर वेतनमान के साथ त्वरित स्थाई बहाली हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं महिला विकास और सशक्तिकरण हेतु पूर्णरूपेण न्याय प्राप्ति हेतु आज ग्यारहवां दिन है हड़ताल का । किन्तु अब तक किसी भी प्रकार से किसी जवाबदेही महोदय का आगमन या संदेश/ सूचना-सम्पर्क आदि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वालंटियर से, नहीं किया गया है। संघर्ष जारी रहेगा निरंतर।

महिला न्याय की बात और धरातलीय स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार कि योजनाओं का क्रियान्वयन होना, वर्तमान स्थिति में, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो वर्तमान में चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वालंटियर को, सड़क पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज उपस्थित चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वालंटियर महिला स्वयं सेविका कल्याण समिति जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष श्रीमती तोहिमा बन्जारे एवं अन्य गीता साहू, सुनीता मानिकपुरी, मधु भारती, हेमा कश्यप, ज्योति भारती, जागेश्वरी बन्जारे, मधु पटेल, ज्योति भारती, ममता चंद्राकार, ज्योति तिवारी, धनेश्वरी साहू, लक्ष्मी यादव, गायत्री विश्वकर्मा, पूजा मानिकपुरी, नूतन सिंह, बिना महिवाल, निर्मला साहू, हेमा बांधे, नंदनी निर्मलकर, गायत्री बंजारे, सावित्री वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा एवं समस्त अन्य थाना एवं चौकी की उपस्थित चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वालंटियर शामिल हैं।

लाटरी के माध्यम से 15 हितग्राहियों को हुआ प्रधानमंत्री आवास का आबंटन

बेटे से निकलवाया लाटरी, मिला ग्राउंड फ्लोर में आवास

रिसाली (प्रमोदन)। रिसाली निगम के लक्ष्मीनगर में बने प्रधानमंत्री आवास का आवंटन लॉटरी निकालकर किया गया। एक हितग्राही ने अपने तीन साल के मासूम बेटे से लॉटरी पर्ची निकलवाया। उसे भूतल में आवास मिला। महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में 15 हितग्राहियों को आवास आवंटन किया गया। मोर मकान मोर आस घटक के तहत नगर पालिक निगम रिसाली के लक्ष्मीनगर में बने आवास का आवंटन आयुक्त आशीष देवांगन के मार्गदर्शन में किया गया। हितग्राहियों की संख्या कम होने की वजह से 36 आवास में केवल 15 का आवंटन किया गया।

आयुष्मान एवं श्रम कार्ड के लिए शिविर का आयोजन रिसाली निगम द्वारा किया जा रहा है, शुरूआत जोरातराई से

रिसाली (प्रमोदन)। रिसाली निगम आम लोगों का आधार अपडेट करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने रिसाली निगम क्षेत्र के अलग.अलग वार्डो में शिविर लगाया जा रहा है। निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने बताया कि आमतौर पर आधार अपडेट नहीं होने से आयुष्मान कार्ड बनाने में समस्या आ रही थी। यही वजह है कि वार्डवार आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही आधार अपडेट करने शिविर लगाने निर्देश दिए है।

यहां लगेगा शिविर : 12 जुलाई को वार्ड 21 सूर्या नगर के सामुदायीक भवन व वार्ड 05 एचएससीएल कालोनी के शिव मंदिर, 13 जुलाई को वार्ड 14 मरोदा कैंप के बम भोले चौक, वार्ड 15 मौहारी भाठा के शिव मंदिर चौक, 14 जुलाई को वार्ड 35 व 36 डुण्डेरा के लिए वार्ड कार्यालय में शिविर लगाया जाएगा। इसी तरह 15 जुलाई को पुरैना के तीनों वार्ड के लिए सामुदायीक भवनए 16 जुलाई को वार्ड 22 मैत्रीकुंज के मंगल भवन, वार्ड 23 प्रगतिनगर के शिव मंदिर, 18 जुलाई को वार्ड 16 से 21 तक के लिए मरोदा चैपाटी, 19 जुलाई को वार्ड 19 विजय चौक व तालपुरी बी ब्लाक, 20 जुलाई को वार्ड 30 इस्पात नगर के सांई मंदिर व वार्ड 34 नेवई बस्ती के दुर्गा मंच, 21 जुलाई को वार्ड 8 रिसाली सेक्टर के इस्पात क्लब, वार्ड 09 के दशहरा मैदान मंच व 22 जुलाई को वार्ड 26, 29, 30, 31 के लिए सांस्कृतिक भवन मंच, 23 जुलाई को वार्ड 06 के लिए रूआबांधा स्थल, वार्ड 07 रिसाली सेक्टर के लिए शिव मंदिर, 24 जुलाई को वार्ड 2, 3, 4 के लिए यादव चौक, 25 जुलाई को वार्ड 10 के लिए दशहरा मैदान व 29 जुलाई को वार्ड 11 व 12 के लिए इस्पात क्लब में शिविर लगाया जाएगा।

पीएम आवास आबंटन के लिए 13 को लाटरी

भिलाई (प्रमोदन)। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एचपी किफायती आवास मोर मकान मोर आस घटक तथा मोर मकान मोर चिन्हारी घटक के अंतर्गत किराएदारी में निवास करने वाले एवं केनाल रोड आदि से प्रभावित लोगों को आवास प्रदान करने के लिए 13 जुलाई 2023 को 10. 30 बजे लाटरी पद्धति से आवास आवंटन किया जाएगा। लॉटरी में शामिल होने के लिए हितग्राही को अपना अंशदान जमा रसीद की मूल प्रति, मूल आधार कार्ड, आवेदन पत्र की पावती तथा लॉटरी में शामिल होने हेतु जारी सूचना पत्र के साथ निर्धारित स्थल एवं निर्धारित समय में स्वयं उपस्थित होना होगा। योजना के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि हितग्राही दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक हो तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवास शाखा कक्ष क्रमांक 16 में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करेंगे।

शासन द्वारा संचालित योजनाओं से अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही हो लाभान्वित : के.पी. खाण्डे

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की

▶▶ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत राहत योजना का हो व्यापक प्रचार-प्रसार

दुर्ग (प्रमोदन)। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और अनुसूचित जाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली। अध्यक्ष श्री खाण्डे ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राहत योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार.प्रसार करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित करने का आहवान किया। बैठक में छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सचिव बी.एल. बंजारे, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, प्रभारी सहायक आदिवासी विकास श्रीमती प्रियवंदा रामटेके सहित अन्य विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने अनुसूचित जाति आयोग के गठन के उद्देश्य, कर्तव्यों एवं शक्तियों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लोगों के प्रति कोई अन्याय या अपराध न हो इसके लिए हमें संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। उन्होंने इसके लिए लोगों को भी जागरूक करने पर भी जोर दिया।

अध्यक्ष श्री खांडे ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा इस जाति के लोगों को जागरूक भी किया जाए ताकि वे शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रुप से पीड़ित हितग्राही को न्याय दिलाने एवं शासन की योजनाओं के तहत उन्हे मिलने वाली सहायता राशि से लाभान्वित करने की बात कही। प्रभारी सहायक आयुक्त श्रीमती प्रियंवदा रामटेके ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत जिले में छात्रावास की सुविधा, अंर्तजातीय विवाह, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शाला आश्रमों की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, शिक्षा, पुलिस, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, कृषि तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के संबंध में अवगत कराया।

जब भी जरूरत पड़ी भसीन जी हमेशा साथ खड़े रहे : भोला साहू

वार्ड-32 में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, पुत्री सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हुए

भिलाई (प्रमोदन)। 8 जुलाई को वार्ड नंबर 32 बैकुंठ धाम में बैकुंठ धाम समिति संस्थापक राजेंद्र सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया।

आज के कार्यक्रम में उपस्थित स्व. विद्यारतन भसीन की पुत्री दिव्या भसीन विशेष रूप से उपस्थित थी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साहू समाज के युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष भोला साहू ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया एवं कहा कि भसीन जी जब भी जरूरत पड़ी हमेशा सबके साथ खड़े रहे एवं जिस चीज की जरूरत पड़ी भवन हो या सड़क कभी उन्होंने निराश नहीं किया। कार्यक्रम में उपस्थित पार्षद प्रियंका साहू, पूर्व पार्षद रिंकू प्रसाद, आरती सोनवानी, भाजपा नेता त्रिलोचन सिंह, त्रिलोकीनाथ पांडे, राजेश प्रसाद, बंटी सिंह, रजत ओझा, सुरेंदर सुरेंद्र, जस्सू सिंह, मन्मथ कुमार एवं समस्त मोहल्ले वासी काफी संख्या में उपस्थित थे।

शंकराचार्य विवि में बिहेवियर क्लब देखने पहुंची यूनीसेफ और USAID की टीम, यूनिवर्सिटी परिसर में अतिथियों का गर्मजोशी से हुआ स्वागत

भिलाई (प्रमोदन)। यूनिसेफके तकनीकि मार्गदर्शन में अलायन्स फॉर बिहेवियर चेंज और शंकराचार्य प्रोफेशनल युनिवर्सिटी भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे बिहेवियर क्लब को देखने यूनिसेफऔर USAID की केंद्रीय टीम भिलाई स्थित यूनिवर्सिटी परिसर पहुंची। बिहेवियर क्लब (घासीदास यूनिवर्सिटी) के कॉर्डिनेटर तुपेंद्र साहू ने यूनिसेफ और USAID के अधिकारियों को बिहेवियर क्लब के चरणबद्ध कार्य को दिखाया। घासीदास यूनिवर्सिटी के क्लब मेंबर राहुल तिवारी ने खुशी नामक बिहेवियर क्लब के सोशल एक्सपेरिमेंट के अनुभव को साझा किया। वहीं शंकराचार्य यूनिवर्सिटी की वंदना ने क्लब के अनुभव को साझा किया। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के एसबीसी कंसल्टेंट चंदन कुमार ने बताया कि किस तरह रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित करके क्लब के मेंबर की समझ को विकसित करते हैं। इस मौके पर आई यूनिसेफ एसबीसी इंडिया चीफ सुश्री तमारा अबू शाम काफी उत्साहित दिखी और उन्होंने उपस्थित स्टूडेंट को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आकर बेहतर जाना कि अलायन्स और बिहेवियर क्लब कितना महत्वपूर्ण है । इस मौके पर USAID इन्डिया की सीनियर एसबीसी सलाहकार कोमल खन्ना, यूनिसेफ एसबीसी स्पेशलिस्ट फॉर वाश प्रोग्राम प्रमुख शालिनी प्रसाद, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के एसबीसी स्पेशलिस्ट अभिषेक सिंह, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के एसबीसी कंसल्टेंट चंदन कुमार भी उपस्थित थें। इससे पूर्व यूनिवर्सिटी में आगमन पर यूनिसेफ और USAID की टीम का स्वागत अलायन्स फॉर बिहेवियर चेंज के स्टेट नोडल इन चार्ज मनीष सिंह, अलायन्स के जोनल हेड शरद श्रीवास्तव, अलायन्स के दुर्ग जिला हेड अजय देशमुख, नोडल पार्टनर गायत्री सिंह, यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन विभाग प्रमुख डॉ. धनेश जोशी ने संयुक्त रूप से किया । अलायन्स की तरफ से यूनिसेफ एसबीसी इंडिया चीफ सुश्री तमारा अबू शाम को बुके देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात बोर्ड रूम में यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ ए के झा एवं पी के मिश्रा कुलसचिव ने यूनिवर्सिटी की तरफ से स्वागत किया गया। श्री मिश्रा ने क्लब के महत्व पर बात करते कहा कि बिहेवियर क्लब के छात्रों के लिए ऐसी प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से वे न केवल स्वयं के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते है अपितु समाज के नकारात्मक व्यवहार को सकारात्मकता में बदल सकते हैं साथ ही उन्होंने क्लब के सदस्य छात्राओं से कहा कि जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वह परिवर्तन आप स्वयं में लाइये। तत्पश्चात यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के एसबीसी स्पेशलिस्ट अभिषेक सिंह ने क्लब की प्रासंगिकता पर जानकारी दी। अलायन्स के स्टेट नोडल इन चार्ज मनीष सिंह ने अलायन्स के कार्य को बताया और जोनल हेड शरद श्रीवास्तव ने अपने बेहतर अनुभव को बताया। इस अवसर पर बिहेवियर क्लब (शंकराचार्य विवि) कॉर्डिनेटर भानू प्रिया कमल, घासीदास यूनिवर्सिटी और शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के करीब 35 स्टूडेंट मौजूद रहें।

वीरांगना रानी अवंतिबाई लोधी स्मृति पुरस्कार

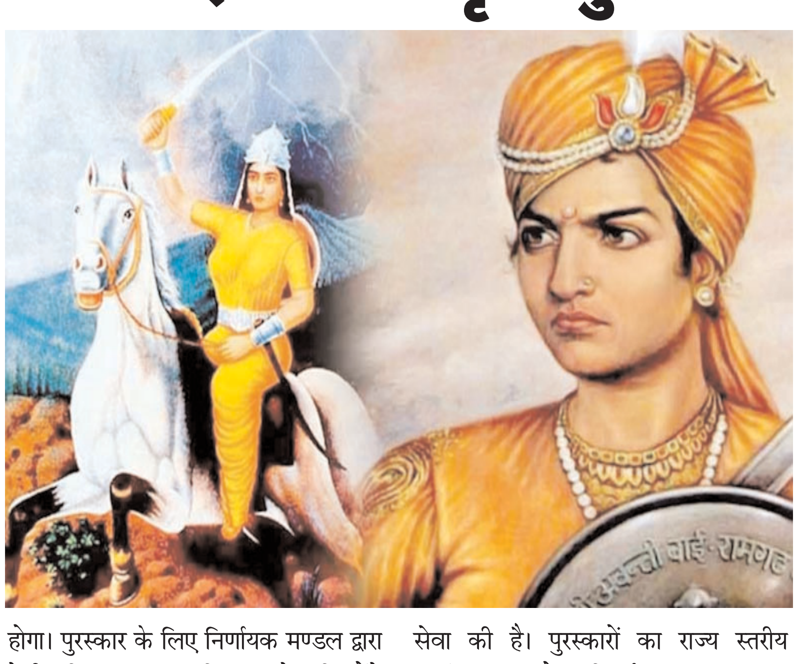

दुर्ग (प्रमोदन)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से **वीरांगना रानी अवंतिबाई लोधी स्मृति पुरस्कार** देने का निर्णय लिया गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना 15 मार्च 2023 को प्रकाशित किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन के अनुसार यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल द्वारा चयन होने पर निर्णय के आधार पर पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये नगद व चेक के रूप में सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जावेगा। पुरस्कार हेतु आयुसीमा का बंधन नहीं होगा। पुरस्कार के लिए निर्णायक मण्डल द्वारा ऐसी महिला का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य में वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की है। पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगाए जिसमे भाग लेने के लिए चयनित महिला को आमंत्रित किया जावेगा।

बहादुर कलारिन सम्मान पुरस्कार, मिलेंगे 2 लाख

दुर्ग (प्रमोदन)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहादुर कलारिन सम्मान देने का निर्णय लिया गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना 18 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन के अनुसार यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल द्वारा चयन होने पर निर्णय के आधार पर पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये नगद व चेक के रूप में, सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जावेगा। पुरस्कार हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। पुरस्कार के लिए निर्णायक मण्डल द्वारा ऐसी महिला का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहन के क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की है।

पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित महिला को आमंत्रित किया जावेगा।

सकारात्मक बदलाव में दुर्ग के दूत बने युवा

▶▶ दुर्ग जिले के सर्वांगीण विकास के लिए दुर्ग के दूत कार्यक्रम में अपना संपूर्ण योगदान देने अधिकारियों ने ली शपथ

दुर्ग (प्रमोदन)। जिला प्रशासन के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा युवोदय दुर्ग के दूत कार्यक्रम का आयोजन लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में किया गया। युवोदय दुर्ग के दूत कार्यक्रम समुदाय के द्वारा समुदाय के लोगों के लिए शुरू की गई स्वयंसेवा की एक पहल है। यह स्वयंसेवकों को एएनसी चेकअप, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, किशोर किशोरियों का संपूर्ण स्वास्थ्य एवं विकास, पर्यावरण में युवाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व और नशामुक्ति जैसे क्षेत्रों के प्रति लोगों को जागरूक करने और जिले में अपनी सेवा देने के अवसर प्रदान करेगा। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा सहित सभी अधिकारी एवं युवोदय दुर्ग के दूत के युवा स्वयंसेवकों द्वारा दुर्ग जिले के सर्वांगीण विकास के लिए दुर्ग के दूत कार्यक्रम में अपना संपूर्ण योगदान देने की शपथ ली। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन स्तर पर हर संभव मदद की जाएगी। आम लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर रोहित व्यास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्वनी देवांगन, संयुक्त कलेक्टर गोकुल राउटे, यूनिसेफप्रमुख जॉब जकारिया उपस्थित थे। आने वाली पीढ़ी को युवा नेतृत्व के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे हिंसा, नशे, एवं किसी भी मादक पदार्थ के सेवन को समाप्त किया जा सके। मानसिक विषय को चर्चा मे लाना एवं स्वयंसेवा की भावना को बढ़ावा देने से समाज स्वस्थ एवं सुरक्षित व्यवहारों को अपना सकता हैं। जिला प्रशासन दुर्ग एवं यूनिसेफके तत्वावधान में एवं जनभागीदारी के मूल मंत्र पर आधारित यह कार्यक्रम एएनसी चेकअप, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्यए किशोर किशोरियों का संपूर्ण स्वास्थ्य एवं विकास, पर्यावरण में युवाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व, नशीली पदार्थों के रोकथाम हेतुए समाज एवं युवाओं का योगदान जैसे विषयों पर सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन करने जा रही है ।

किसी भी समाज, वर्ग, जाति, समुदाय, व्यवसाय से आने वाले 15 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जो अपनी योग्यता एवं रुचियों के आधार पर इन विषयों में लोगों एवं अपने समाज मे बदलाव लाने को इच्छुक है, वह सभी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं।

इसका कार्यक्षेत्र : गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) जांच को बढ़ावा देना, स्वयंसेवक द्वारा गर्भवती महिलाओं या नई माताओं को फॉलो अप कॉउसेलिंग के लिए प्रेरित करना, किसी भी प्रकार के हिंसा को रोकना, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ, समुदाय मे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देनाए किशोर. किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य और एनीमिया पर जागरूक करना, बाल विवाह को समाप्त करना एवं कम उम्र की शादी को रोकना, युवाओं के बीच प्रजनन और यौन स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना, पर्यावरण मे युवा नेतृत्व, उनके बीच मिशन लाईफ के व्यवहारों को प्रेरित करना जन.भागीदारी हेतु यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज मे सम्मिलित करना, युवाओं के लिए विचार, नवाचार को रखने के लिए मंच निर्वाण करना, स्कूल और कॉलेज स्तर पर युवाओं के बीच नशे एवं किसी भी मादक पदार्थ के सेवन को रोकना, व्यवहार परिवर्तन हेतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ऑफ़लाइन ब्रांडिंग का लाभ उठाना। यूनिसेफ़ का कार्य तकनीकि सहायता प्रदान करना, बीआई संदेशों को डिजाइन करना, ब्रांडिंग और आईइसी क्षमता निर्माण, निगरानी, मूल्यांकन और डाक्यूमेन्टैशन करना यह एक ऐसा मंच है, जो किसी भी धार्मिक, राजनीतिक या किसी भी संस्था से प्रेरित नहीं है । यह जिले के लोगों द्वारा अपने समुदाय के बेहतरी के लिए शुरू की गई पहल है। किसी भी वर्ग, धर्म जाति, समुदाय के किशोर-किशोरी के रूप में अपने गांव, समाज, शहर के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। स्वयं सेवा के लिए किसी प्रकार का मानदेय पैसे इत्यादि नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति अपनी इच्छा और निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं।

टेस्ट सीरीज में दो रिकॉर्ड पर रहेगी कोहली की नजर, शतक लगाते ही कर लेंगे ब्रैडमैन की बराबरी

नईदिल्ली,। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 12 जुलाई से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इस सीरीज के पहले मैच में ही अगर टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली रूक कर खेलते है और एक शतक के साथ में 150 रन बना लेते है तो वो दो रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। ऐसे में इस टेस्ट में उनके सामने दो रिकॉर्ड है जिनकी वो जरूर बराबरी करना चाहेंगे।

अगर विराट कोहली पहले टेस्ट में शतक लगा देते हैं तो वह टेस्ट में 29 शतक पूरे कर लेंगे। अगर वो 29वां शतक लगा देते है तो वह सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दसवें नंबर पर पहुंच जाएंगे। साथ ही महान डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर लेंगे। ब्रैडमैन पहले ही 29 शतक लगा चुके हैं।

इसके साथ ही अगर विराट कोहली पहले टेस्ट में 150 रन बना लेते हैं तो वह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में जैक कैलिस को पीछे छोड़कर पांचवें स्थान पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दे की तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कोहली ने फिलहाल 25,385 रन बनाए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के कैलिस के नाम 25,534 रन दर्ज हैं।

जून 2025 तक न्यूजीलैंड पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे गैरी स्टीड

वेलिंगटन। गैरी स्टीड जून 2025 तक न्यूजीलैंड पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट (हुंष्ट) ने उनके साथ दो साल का अनुबंध विस्तार किया है।

स्टीड को पहली बार 2018 के अंत में दो साल के लिए नियुक्त किया गया था, इसके बाद उनका अनुबंध 2020 में भारत में आगामी वनडे विश्व कप के अंत तक नवीनीकृत किया गया था,हालांकि अब उनका कार्यकाल जून 2025 में चल रहे विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र के समापन तक रहेगा। इस साल विश्व कप के बाद, स्टीड की विस्तारित अवधि में अगली गर्मियों में टी20 विश्व कप, 2025 की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के क्वालीफाई होने पर 2025 में डब्ल्यूटीसी फाइनल शामिल होगा। एनजेडसी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय एक लंबी और गहन परामर्श प्रक्रिया के बाद लिया गया था जिसमें स्टीड को विस्तार के लिए सर्वसम्मति से समर्थन मिला था।

एनजेडसी के जीएम हाई परफॉर्मेंस ब्रायन स्ट्रोनैच ने कहा, गैरी के लिए समर्थन बेहद सकारात्मक था। खिलाड़ियों, ब्लैककैप्स सपोर्ट स्टाफ, मेजर एसोसिएशन कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ-साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन और एनजेडसी हाई परफॉर्मेंस यूनिट स्टाफ ने गैरी का पूर्ण समर्थन किया। गैरी के परिणाम बहुत प्रभावशाली रहे हैं और हमें विश्वास है कि उनके पास अभी भी टीम को देने के लिए बहुत कुछ है। स्ट्रोनैच ने चौथे कोच की अवधारणा के बारे में भी बात की, जिसमें न्यूजीलैंड दौरे वाली टीमों को विशेषज्ञ कौशल या विशिष्ट विदेशी वातावरण या प्रारूपों का ज्ञान वाले कोचों द्वारा समर्थन दिया जाएगा।

ग्लोबल मार्केट में तेजी के संकेत, एशिया में भी हरियाली

नई दिल्ली। लगातार तीन कारोबारी दिन तक गिरावट का सामना करने के बाद ग्लोबल मार्केट से आज मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले कारोबारी सत्र के दौरान बढ़त के साथ बंद हुए। इसी तरह यूरोपीय बाजार के तीनों सूचकांक भी ग्रीन जोन में बंद होने में सफल रहे। एशियाई बाजारों में भी आज लगातार खरीदारी होती नजर आ रही है।

पिछले कारोबारी सत्र के दौरान वॉल स्ट्रीट में उत्साह का माहौल नजर आया। डाओ जोंस 209.52 अंक यानी 0.62 प्रतिशत की मजबूती के साथ 33,944.40 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एसएंडपी 500 इंडेक्स ने 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,409.53 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 0.18 प्रतिशत चढ़कर 13,685.48 अंक के स्तर पर बंद हुआ। जानकारों का मानना है कि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान वॉल स्ट्रीट में उत्साह का माहौल जरूर रहा, लेकिन निवेशक अभी भी ब्याज दरों को लेकर आशंकित हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (यूएस फेड) की अगली बैठक 25 और 26 जुलाई को होने वाली है, जिसमें ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा। यूएस फेड की ओर से पहले ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का संकेत दिया जा चुका है। इसलिए निवेशक सतर्क होकर कारोबार कर रहे हैं। कल ही अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। वॉल स्ट्रीट की नजर महंगाई के आंकड़ों पर भी रहेगी। इसलिए पिछले कारोबारी सत्र में भले ही वॉल स्ट्रीट के तीनों सूचकांकों ने ग्रीन जोन में अपना कारोबार खत्म किया, लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिकी बाजार में उतार-चढ़ाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

यूरोपीय बाजार भी पिछले कारोबारी सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 7,273.79 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स में 0.45 प्रतिशत की छलांग लगाकर 7,143.69 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,673.16 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में भी आज सुबह से ही मजबूती नजर आ रही है। एशिया के सभी 9 बाजारों के सूचकांक बढ़त के साथ ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 19,501 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 6.33 प्रतिशत मजबूत होकर 32,297.21 अंक तक पहुंच गया है।

हुंडई की सबसे सस्ती एसयूवी भारत में लॉन्च, 5.99 लाख में उपलब्ध

नई दिल्ली। इस साल भारत में लॉन्च होने वाली बहुप्रतीक्षित कार हुंडई एक्सटर, प्रसिद्ध कोरियन ब्रांड की सबसे किफायती एसयूवी होने के अपने दावों के साथ काफी उत्साह पैदा कर रही है. अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद, एक्सटर में स्टाइल है और यह कई प्रभावशाली विशेषताओं से भरा हुआ है. हुंडई एक्सटर का शुरुआती मुल्य 5,99,900 रुपये है. अपने प्रतिद्वंद्वियों के समान, हुंडई एक्सटर में एक कॉम्पैक्ट हैचबैक का पदचिह्न है, लेकिन इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत स्टाइलिंग तत्व हैं. इसके बाहरी डिज़ाइन में आगे और पीछे फॉक्स स्किड प्लेट, बंपर पर बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्क के ऊपर बॉडी मोल्डिंग की सुविधा है. एक्सटर एच-आकार के डे-टाइम रनिंग एलईडी और एलईडी प्रोजेक्टर के साथ एक स्प्लिट हेडलैंप सेटअप भी दिखाता है, जो सामने एच-आकार के एलईडी इंसर्ट जैसा दिखता है. सुविधाओं के संदर्भ में, एक्सटर में एक पुश स्टार्ट-स्टॉप बटन, ऊंचाई-समायोज्य ड्राइवर की सीट, सिंगल-पेन सनरूफ (सेगमेंट-फर्स्ट), वायरलेस चार्जर, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, रियर एसी वेंट, पैडल शिफ्टर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और शामिल हैं. सुरक्षा सुविधाओं में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक रियर कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण और हिल होल्ड असिस्ट शामिल हैं. हुंडई एक्सटर 1.2-लीटर चार-सिलेंडर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है.

ग्राहक एक्सटर के लिए नौ रंग विकल्पों में से चुन सकते हैं, जिसमें छह मोनोटोन और तीन डुअल-टोन संयोजन शामिल हैं- एटलस व्हाइट, कॉस्मिक ब्लू, फ़ायरी रेड, रेंजर खाकी, स्टारी नाइट, टाइटन ग्रे, एटलस ब्लैक विद एबिस ब्लैक, कॉस्मिक ब्लू विद एबिस ब्लैक , और एबिस ब्लैक के साथ रेंजर खाकी।

फिल्म जवान का टीजर जारी, शाहरुख खान का दिखा धांसू अवतार

जवान का ट्रेलर आखिरकार अब रिलीज हो गया है। एटली द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म में शाहरुख खान और नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म पहली बार नयनतारा के साथ शाहरुख खान के मिलन का प्रतीक है। और यह अंतत: यहाँ है! काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निर्माताओं ने 10 जुलाई को शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का ट्रेलर जारी कर दिया। वे इसे प्रीव्यू कह रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है, यह काफी दिलचस्प लग रहा है।

पठान की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद यह सुपरस्टार की दूसरी फिल्म है। एटली द्वारा निर्देशित यह फिल्म पहले 2 जून को रिलीज होने वाली थी, हालांकि, इसे सितंबर में रिलीज करने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इससे पहले एक ट्वीट में शाहरुख ने खबर साझा की थी कि जवान का प्रीव्यू 10 जुलाई 2023 को सुबह 10:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। वादे के अनुरूप, यह अंतत: यहाँ है! ट्रेलर में शाहरुख कहते हैं मैं कौन हूं? कौन नहीं। पता नहीं। मां को किया वादा हूं या अधूरा एक इरादा हूं। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं - ये खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूँ। ट्रेलर में हम शाहरुख को जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए देख रहे हैं। उनका लुक भी कुछ दिलचस्प है। लघु वीडियो में नयनतारा की एक झलक भी मिलती है। हम दीपिका पादुकोण को बारिश के नीचे लाल साड़ी में एक एक्शन सीन करते हुए भी देखते हैं। अंत में शाहरुख खान भी गंजे लुक में नजर आते हैं।

अभिषेक और सैयामी की फिल्म घूमर पहुंची इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न

पिछले कुछ दिनों से फिल्म घूमर सुर्खियों में हैं। पिछले महीने इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और सैयामी खेर की पहली झलक सामने आई थी। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह इसलिए भी है क्योंकि इसके निर्देशन की जिम्मेदारी आर बाल्की पर है, जो चीनी कम, पा और मिशन मंगल जैसी कई बेहतरीन फिल्में दर्शकों के बीच पेश कर चुके हैं। अब खबर है कि उनकी फिल्म घूमर को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में दिखाया जाएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) में घूमर का प्रीमियर होने वाला है। यह फेस्टिवल 12 अगस्त से शुरू होगा और इसकी शुरुआत घूमर की स्क्रीनिंग के साथ ही होगी। अभिषेक और सैयामी के अलावा इस फिल्म में शबाना आजमी और अंगद बेदी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और मेलबर्न को स्पोर्ट्स का मक्का कहा जाता है। घूमर के जरिए एक शारीरिक रूप से अशक्त खिलाड़ी की प्रेरणादायी यात्रा दर्शकों के बीच आएगी। सैयामी ने फिल्म के अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, स्क्रीन पर खेलना हमेशा मेरे लिए एक सपना रहा। जब से मैं एक्टिंग की दुनिया में आई हूं, तभी से इसकी इच्छा रही है। मेलबर्न में फिल्म के प्रीमियर को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। सैयामी ने बताया कि दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न मेलबर्न के ही रहने वाले थे, जो हमेशा उनके पसंदीदा खिलाड़ी रहे, इसलिए भी वह इस शहर में फिल्म के प्रीमियर को लेकर खुश हैं। बाल्की और अभिषेक ने कहा, घूमर विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने और चुनौतियों का सामना करने की कहानी है। वे इस आईएफएफएम के लिए फिल्म के चुने जाने से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक, खेल जीवन को जीने लायक बनाता है। शबाना प्रीमियर के दौरान समारोह में उपस्थित रहेंगी। इस फिल्म में वह सैयामी की दादी का किरदार निभा रही हैं, जो खुद क्रिकेट की दीवानी है और परिवार के विरोध के बावजूद अपनी पोती के सपनों को पूरा करने में उसका पूरे दिल से समर्थन करती है।

बिग बॉस' में वही रह सकता है, जो राजनीति का आदी हो : आरती सिंह

'बिग बॉस 13' की कंटेस्टेंट रह चुकी आरती सिंह ने शो में रहने के लिए एक आसान जगह नहीं होने पर अपने विचार साझा किए हैं।

हाल ही के एक एपिसोड के दौरान, साइरस ब्रोचा ने कहा कि वह 'बिग बॉस ओटीटी 2' के घर के अंदर रहने के दबाव से नहीं निपट सकते और उन्होंने बिग बॉस के साथ-साथ होस्ट सलमान खान से उन्हें चल रहे रियलिटी शो से बाहर निकलने की अनुमति देने का आग्रह किया।

हालांकि, सलमान और बिग बॉस ने उनसे कहा कि जब तक दर्शक उन्हें शो से बाहर नहीं कर देते, तब तक उनके पास यह विकल्प नहीं है

आरती सिंह ने साइरस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिग बॉस का घर वास्तव में लोगों को बर्बाद कर सकता है, खासकर उन लोगों को जो राजनीति में माहिर नहीं हैं या उनमें धैर्य की कमी है।

उन्होंने कहा, यह उन लोगों के लिए बहुत थका देने वाला हो सकता है जो राजनीति के आदी नहीं हैं और उनमें धैर्य की कमी है। वे फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं और छोड़ना चाहते हैं। हालांकि हार न मानने में ही उनकी ताकत है।

उन्होंने कहा, उन्हें किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है, यह उनकी अपनी यात्रा है।

कलेक्टर और एसपी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा

दुर्ग (प्रमोदन)। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा नें आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर श्री मीणा नें वाहन दुर्घटना पश्चात उत्पन्न स्थिति से निपटने अधिकारियों को विभागीय समन्वय के साथ कार्यवाही करते हुए नागरिकों को समझाइस देने की सलाह दी। पुलिस अधीक्षक श्री सिन्हा नें आक्रोषित भिड़ को नियंत्रित करने के उपाय बताये। उन्होनें अधिकारियों को धारा 107.16 को बेहतर डंग से उपयोग में लाने कहा। बैठक में विगत दिवस जिले के विभिन्न स्थानों में विघटित घटनाओं के कारणो एवं समाधान के उपाय पर भी चर्चा की गई। साथ ही आने वाले दिनों में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इस पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अरविंद एक्का सभी एसडीएम तथा ए.एस.पी., सी.एस.पी. सहित विभिन्न थानों के टीआई उपस्थित थे।

कलेक्टर जनदर्शन : अवैध प्लाटिंग पर करें शीघ्र कार्यवाही

दुर्ग (प्रमोदन)। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में राजस्व एवं नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, भिलाई नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास, दुर्ग नगर निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर व रिसाली नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन के साथ एसडीएम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री मीणा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जमीन से जुड़े सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, नक्शा बटांकन, डायवर्सन की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय प्रकरणों के निराकरण में अपने दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च प्राथमिकता से करने को कहा। कलेक्टर श्री मीणा ने अवैध प्लाटिंग के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत कार्यवाही करें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्ण हो चुके आवासों की जानकारी ली। इस पर नगर पालिक निगम आयुक्त ने बताया कि दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रगतिरत है और अधूरे कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जा रहा है। साथ ही कलेक्टर ने नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत रोड मरम्मत की जानकारी ली। बाजारों को व्यवस्थित करने के लिए बाजार स्थल में पार्किंग व्यवस्थाए शौचालय एवं सीसी टी.वी. कैमरा एवं प्रकाश की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

वृक्षारोपण का कार्य शीघ्र पूर्ण करें

नगरीय निकाय में वृक्षारोपण हेतु ट्री गार्ड एवं पौधे की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए कहा कि शहर को हरा.भरा करने के लिए सभी मुख्य मार्ग, शासकीय बिल्डिंग, मार्केट, दुकानों, कॉलोनियों एवं घर.घर में सभी खाली जगहों में पौधे लगाए जाएंगे। जगह के हिसाब से कन्हेर, बोगनविलिया के छोटे, फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाते हुए वृक्षारोपण के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने शासकीय भवनों के बाहर बोगनविलिया लगाने के निर्देश दिए। दुर्ग नगर निगम ने वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वन होम वन ट्री अभियान शुरू किया हैए जिसके अंतर्गत निगम द्वारा निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराया जा रहा है। वेंडिंग जोन के कार्यो की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने वेंडिंग जोन के आसपास छोटे.छोटे पौधे लगाने को कहा। साथ ही उन्होंने मोर मकान मोर आसए मोर मकान मोर चिन्हारी में प्रगतिरत आवासों की जानकारी ली।

निर्वाचन की समीक्षा

कलेक्टर ने अधिकारियों से निर्वाचन कार्यो के संबंध में चर्चा करते हुए सभी अधिकारियों को आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए जिले में थर्ड जेंडर, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में शीघ्र जोड़ने को कहा। मतदाताओं का सत्यापन से संबंधित एवं मतदान केन्द्र में रेम्पए शौचालय एवं पानी की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु मतदाताओं का सत्यापन करने को कहा।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरूआत 17 जुलाई से

बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक तीन आयु वर्ग के प्रतिभागी ले सकेंगे हिस्सा

दुर्ग (प्रमोदन)। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक 2023.24 का आयोजन हरेली त्योहार के दिन 17 जुलाई से शुरू किया जाएगा। छत्तीसढ़िया ओलंपिक 6 चरणों में लगभग ढ़ाई महीने तक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने और उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा खेल भावना का विकास करने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक विलियम लकड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में 16 तरह के पारम्परिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सीकूद एवं कुश्ती को भी जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा गया है। प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर 2023 को होगा। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेल में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो.खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसी खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लम्बी कूद, रस्सी कूद एवं कुश्ती शामिल हैं।

छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का आयोजन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर प्रतियोगिता 17 जुलाई से 22 जुलाई तक नॉकआउट पद्धति से होगा। वहीं दूसरा जोन स्तर है, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक जोन होगा। इसका आयोजन 26 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। विकासखंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर पर आयोजन 7 अगस्त से 21 अगस्त तक होगा। जिला स्तर पर आयोजन 25 अगस्त से 04 सितंबर तक होगा। संभाग स्तर पर आयोजन 10 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जिसका आयोजन 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में आयु वर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तकए दूसरा वर्ग 18.40 वर्ष आयु सीमा तक और तीसरा वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विकासखंड व नगरीय क्लस्टर स्तर पर विजेता प्रतिभागियों से लेकर राज्य स्तर के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। विकासखंड व नगरीय क्लस्टर स्तर प्रथम आने वाल विजेता खिलाड़ियों को 1000 रूपएए द्वितीय स्थान आने पर 750 रूपए एवं तीसरा स्थान आने पर 500 रूपए की पुरस्कार राशि एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह जिला स्तर पर प्रथम आने वाल विजेता प्रतिभागियों को 2000 रूपए की राशिए द्वितीय आने पर 1500 रूपए और तीसरे स्थान आने पर 1000 रूपए की राशि सहित प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। संभाग स्तर पर विजेता प्रतियोगियों को प्रथम आने पर 3000 रूपएए द्वितीय आने पर 2500 रूपए एवं तीसरे स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को 2000 रूपए एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तर पर ओलंपिक के अंतिम आयोजन में प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को 5000 रूपए, द्वितीय आने पर 4500 रूपए एवं तीसरे स्थान आने वाले खिलाड़ियों को 4000 रूपए की राशि और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

150 प्रतिभागियों में प्राप्त किया पहला स्थान

आईआईटी गुवाहटी में सेजेस घुघवा के बच्चों ने लहराया परचम

बच्चों ने बनाया पेट्रोल चोरी रोकने का यंत्र, देशभर के इनोवेर्टस ने की सराहना

दुर्ग (प्रमोदन)। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम घुघवा ने छात्रों ने पेट्रोल की चोरी रोकने के लिए एक अनोखा यंत्र बनाया जिससे पेट्रोल पंपों द्वारा पेट्रोल की चोरी रोकी जा सके। इस मॉडल को उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल (एमआईसी) एवं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (आईसीटीइ) कि ओर से इनोवेशन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप में प्रस्तुत किया। यह आयोजन 22 जून से 26 जून को देश के 6 जोन में किया गया था जिसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल घुघुवा (क), पाटन के छात्र आयुष जोशी और पुर्वेश निषाद के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट स्मार्ट व्हीकल का चयन आईआईटी असम गुवाहाटी के लिए किया गया था। जिसमे देश के विभिन्न प्रांतों से कॉलेज एवं स्कूल के 60 टीम एवम् 150 छात्रों ने भाग लिया था। जिनमें से इनके द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप स्मार्ट व्हीकल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व भी उन्होंने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ द्वारा आयोजित नेशनल टेक्निकल फेस्ट 2.0 में भी प्रथम पुरुस्कार एवम् 15000 की राशि प्राप्त की थी। विजेताओं को शिक्षा मंत्रालय की ओर से अपने इस प्रोजेक्ट को विकसित करने हेतू अनुदान के अवसर के लिए भी अर्हता प्रदान किया गया। सभी कार्य उनकी शिक्षिका एवं अटल टिंकरिंग लैब प्रभारी श्रीमती मारिया जास्मिन के मार्गदर्शन में किया गया। इस बूटकैम्प में छात्रों को उद्यमिता और नवाचार से संबंधित प्रशिक्षण देश के विख्यात उद्यमीयो एवम वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया जो कि अति महत्वपूर्ण एवम् रोचक रहा।

विधायक-महापौर ने दादा-दादी, नाना-नानी पार्क में नि:शुल्क पौधों का किया वितरण

दुर्ग (प्रमोदन)। नगर निगम की ओर से पर्यावरण जागरुकता अभियान के तहत मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चन्द्राकर और पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा द्वारा दादा दादी.नाना नानी पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक में आए शहर के विभिन्न इलाके के आमजन के बीच निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय में भी पौधा वितरण किया गया। निगम द्वारा शहर ने निरन्तर निशुल्क पौधे बांटे जाएंगे। उद्यान प्रभारी अनिल सिंह द्वारा पौधा वितरण में सहयोग करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अभियान शुरू किया गया है। आज लगभग 349 छायादार, फलदार एवं इमारती पौधा का वितरण किया गया। इधर इस दौरान विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण पेड़ पौधों की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे लगाना जरूरी है। पेड़ पौधों की कमी के कारण ऑक्सीजन लेबल भी कम होता जा रहा है। इस अवसर पर उद्यान प्रभारी अनिल सिंह के अलावा नागरिकगण मौजूद रहें।

राज्यस्तरीय पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का होगा सम्मान : आर.एन. वर्मा

दुर्ग (प्रमोदन)। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर.एन. वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्यकारणी की बैठक 10 जुलाई 2023 में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में एवं पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों के आतिथ्य में रायपुर में छत्तीसगढ़ स्तरीय पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन किए जायेंगे एवं समाज के उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया जायेगा। कार्यकारणी की बैठक में कार्यालयीन कार्यों की समीक्षा की गई एवं शासन को अनुशंसा भेजने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत ओ.बी.सी. के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय की जाने वाली विसंगति को दूर करने एवं ओ.बी.सी. के छात्र छात्राओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति के बराबर करने कहा गया।

इसके साथ ही प्रस्ताव पारित किया गया कि ओ.बी.सी. समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रतिवर्ष ज्योतिबा फूले राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। इसके अतिरिक्त देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले की स्मृति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षिका एवं समाज सेविकाओं को प्रतिवर्ष सम्मानित किये जाने का प्रस्ताव है। कार्यकारणी की बैठक में अध्यक्ष थानेश्वर साहू, सदस्य महेश चंद्रवंशी, आदिम जाति कल्याण विभाग के संचालक श्री गड़ेवाल, सचिव बीरू कुमार साहू, अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे उपस्थित थी।

कृषि विभाग द्वारा कृषि आदान सामग्री विक्रय प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण

दुर्ग (प्रमोदन)। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2023 में जिले के कृषकों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री यथा. खादए बीज एवं कीटनाशक दवाई आदि सुनिश्चित कराने के लिए सघन अभियान चलाते हुए जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में उपसंचालक कृषि, ललित मोहन भगत ने जिला स्तरीय निरीक्षण दल के साथ विगत 5 जुलाई को मेमर्स सतगुरु कृषि केंद्रए उतई के विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के समस्त दस्तावेज स्कंध पंजी, बिल बुक, अनुज्ञप्ति पत्र, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि आदान सामग्री आदि का अवलोकन किया गया। कीटनाशक एवं फफूंदनाशक के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। वर्तमान खरीफ मौसम में अब तक जिले के विभिन्न आदान विक्रय प्रतिष्ठानों से कीटनाशकों के 34 नमूने गुणवत्ता विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कृषि विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में उप संचालक कृषि ललित मोहन भगत के साथ विकासखंड दुर्ग के निरीक्षक नवीन खोबरागढ़े एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनिल कुमार चंद्राकर भी मौजूद थे।

बीआईटी में होगी विभागीय परीक्षा

दुर्ग (प्रमोदन)। छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, सी.अनुभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) द्वारा 1 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक विभागीय परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। विभागीय परीक्षा हेतु भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), दुर्ग को परीक्षा केंद्र नामांकित किया गया है। उपायुक्त दुर्ग संभाग द्वारा भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्ग के प्राचार्य को परिपत्र जारी कर विभागीय परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा अवधि के लिए आवश्यकतानुसार 02 कक्ष आरक्षित करने एवं परीक्षार्थियों की बैठक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करने कहा गया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक दिनेश कुमार पुरवार द्वारा आसमां पब्लिशर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जय स्तंभ चौक रायपुर, छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर एम.आई.जी. सी 2331, हाउसिंग बोर्ड, इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई (छ.ग.) 490026 से प्रकाशित। संपादक : दिनेश कुमार पुरवार
आर.एन.आई. नं. CHHHIN/2015/66673 प्रबंध संपादक बी.एल.देवांगन (पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार) समस्त विवादित मामले का निपटारा दुर्ग न्यायालय क्षेत्र होगा। मोबाइल : 9907849957/9584212617, pramodan1215@gmail.com